महोदया, कांग्रेस के पिछले वर्ष हुए कामराज नगर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजीव गांधी ने गरीबी हटाओ, बेकारी मिटाओ का ऐलान किया था। इस बजट में गरीबी खत्म करने और बेरोजगारी दूर करने की योजनाओं को प्राथमिकता देकर उन्होंने अपनी कथनी को करनी में तब्दील कर दिया है। जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना के तहत हर ऐसे परिवार के एक सदस्य को जो गरीबी की रेखा से नीचे है, रोजगार दिलाने की जो व्यवस्था इस बजट के माध्यम से की गयी है, वह एक स्वागत योग्य कदम है। पूरे देश में जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है—ऐसे बैकवर्ड 120 जिले चुनकर उनमें गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। महोदय, एक सुनियोजित विकास के बुनियादी उद्देश्यों की पूर्ति जिनमें मुख्यत: विकास, आधुनिकीकरण, आत्म-निर्भरता और सामाजिक न्याय सम्मिलित हैं, बजट एक साधन का काम करता है। वर्ष 1989-90 का बजट इन्हीं दीर्घावधि उद्देश्यों को आधार मानकर बनाया गया है। वर्ष 1989-90 के बजट प्रस्ताव विशेष रूप से इन उद्देश्यों के प्रति अभिमुख है: (1) उत्पादक रोजगार का संवर्धन, (2) गरीबों के खपत के स्तरों का संरक्षण, (3) गैर अनिवार्य विलासिता खपत को हतोत्साहित करना, विशेष रूप से यदि वस्तुओं का आयात किया जाता हो, (4) मध्यम आय वाले करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करना, (5) औद्योगिक आधुनिकीकरण और विकास की गति को बनाए रखना और (6) वर्ष 1989-90 के बजटीय घाटे को नियंत्रण में रखना।

महोदया, इस प्रकार यह बजट सर्वहारा वर्ग के लिए उपयोगी, लाभदायक और विकासोन्मुखी है तथा मुद्रास्फीति विरोधक है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री बी०एस० भाटिया के मत में इस बजट की महत्वपूर्ण उपलब्धि इस वर्ष के 11 हजार 30 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट घाटे को कम कर 7 हजार 12 करोड़ रुपए के घाटे का प्रावधान करना है।

1 P.M.

दूसरी विशेषता उन्हीं के हिसाब से इस बजट से सरकार की छवि गरीब वर्ग के समर्थक के रूप में उभरी है, ऐसी उनकी मान्यता है। तीसरे, श्री भाटिया के मतानुसार श्री चव्हाण ने राष्ट्रीय आर्थिक हितों का भी ख्याल रखा है और उन्होंने एक जिम्मेदार बजट प्रस्तुत किया है।. (**समय की घंटी**). अत: मैं कह सकता हूं कि इस बजट में राजस्व और समग्र घाटे में पर्याप्त कटौती से मुद्रा स्फीती दबावों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी व आम खपत की किसी मद को प्रभावित किए बगैर 1,300 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए जाएंगे।... (**व्यवधान**)...

THEa DEPUTY CHAIRMAN: Mr Pachouri, you can continue your speech later on. We now adjourn for lunch and we will meet again at 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the Clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock, the **Vice-Chairman, (Shri Jagesh Desai)** in the Chair.

RESOLUTION RE: INCLUSION OF 'RIGHT TO WORK' IN THE CONSTITUTION AS A FUNDAMENTAL RIGHT—Contd

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH: DESAI): Shri B. Satyanarayan Reddy to continue. Not there. Shri Ratnakar Pandey.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के नौजवान सदस्य श्री अजीत जोगी ने 3 मार्च, 1989 को जो संकल्प इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय उन्होंने जो गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके द्वारा बेरोजगारी की समस्या पर अपना मंतव्य रखा है वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है और उनके मौलिकढंग से सोचने का उदाहरण है।

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

(क) इस समय देश को पेश आ रही सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती बेरोजगारी है;

(ख) देश के रोजगार कार्यालयों में लगभग 3 करोड़ बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं और इतनी ही बड़ी संख्या में व्यक्तियों के नाम दर्ज नहीं हैं;

(ग) न केवल अशिक्षित तथा अकुशल व्यक्तियों बल्कि कुशल तथा शिक्षित व्यक्तियों को भी कोई काम नहीं मिल पाया है; और

(घ) बेरोजगारी के कारण हमारे बेरोजगार युवक कुंठाग्रस्त होते जा रहे हैं और वह कुंठा उन्हें विनाशकारी कार्यों की ओर प्रेरित कर रही है जिसके परिणाम-स्वरूप वे अपनी भावनाओं को अनेक तरीकों से अभिव्यक्त कर रहे हैं ।

देश में सभी योग्य व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार को समुचित प्रशासनिक तथा विधायी उपाय करने चाहियें और इस संदर्भ में यदि आवश्यक हो तो "काम पाने के अधिकार" को संविधान के अध्याय — 3 में सम्मिलित करने हेतु इसे अत्यावश्यक कदम उठाने चाहिए जिससे इसे एक प्रवर्त्तनीय मूल अधिकार बना कर देश के प्रत्येक नागरिक को सांविधिक राहत पहुंचायी जा सके ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, नौजवान बेरोजगार है और जिस देश का नौजवान बेरोजगार होता है उसके दिमाग में खुराफात सूझती है । भूख इंसान को हैवान बना देती है । उपसभाध्यक्ष महोदय, आप अनुभवजन्य हैं उपसभाध्यक्ष के रूप में बैठे हुए है और इस सदन का सभापतित्व कर रहे हैं । आपको पता है गरीब लोग अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कल्पना करते हैं कि हमारा बेटा कलेक्टर होगा, हमारा बेटा दारोगा होगा, हमारा बेटा अध्यापक होगा और उसके लिए अपने खेत-खलिहान और स्थायी सम्पत्ति नारी की जो गहने हैं उनको भी वह गिरवी रख देता है, बेच देता है । नीलाम कर देता है सारी सम्पत्ति को ताकि सन्तान पढ़लिखकर योग्य बने और जब पढ़ने-लिखने के बाद उसे कोई काम नसीब नहीं होता और वह चप्पलें चटखाता हुआ इधर-उधर घसटता है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती, एक-दो जगह नहीं दर्जनों जगह उसे असफलता मिलती है तो उसका मनोबल टूट जाता है । टूटे हुए मनोबल के नौजवान को लेकर किसी देश ने उन्नति नहीं की । हमारे नौजवानों को काम मिलना चाहिए और योग्यता के अनुरूप काम मिलना चाहिए ।

रोजगार कार्यालय में 31 दिसम्बर, 88 तक दर्ज व्यक्तियों की संख्या विभिन्न प्रांतों में क्या है वह मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं । इनको हजार की संख्या में लिया जाए ।

आन्ध्र प्रदेश में 2676.1 बेरोजगार हैं । अरुणाचल प्रदेश में 4.6 बेरोजगार हैं । असम में 903.8 बेरोजगार हैं । बिहार में 2657.6 बेरोजगार है । गोआ में 74.3 बेरोजगार है । गुजरात में 863.3 बेरोजगार हैं । हरियाणा में 577.1 बेरोजगार है । हिमाचल प्रदेश में 367.8 बेरोजगार है । जम्मू और कश्मीर में 129.8 बेरोजगार है और कर्नाटक में 1058.2 बेरोजगार हैं । केरल में 2901.1 बेरोजगार हैं । मध्य प्रदेश में 1788.2 बेरोजगार हैं । महाराष्ट्र में 2663.60 बेरोजगार हैं । मणिपुर में 245.5 बेरोजगार है । मेघालय में 20.5 बरोजगार और मिजोरम में 38.5 बेरोजगार है । नागालैण्ड में 25 बेरोजगार हैं । उड़ीसा में 745 बेरोजगार हैं । पंजाब में 576.1 बेरोजगार राजस्थान में 850.8 बेरोजगार और तमिलनाडु में 2607.6 और त्रिपुरा में 135.6 बेरोजगार है । उत्तर प्रदेश में 2974.5 बेरोजगार हैं । पश्चिम बंगाल में 4188.8 है । केन्द्र शासित क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में 15.1 बेरोजगार है । चण्डीगढ़ में 1427 हैं । दादरा और नागरहवेली में 1.8 हैं दिल्ली में 706.4 बरोजगार है । लक्षद्वीप में 7.8 है । पांडीचेरी में 102.8 बरोजगार हैं ।

इतने करोड़ लोग इस देश में बेकार पड़े हुए हैं और बेकारी और गरीबी ऐसी चीज नहीं हैं कि जो शैविडो में सजा कर

रखी हुई है और उसको खरीद करके या ला करके दूर कर दिया जाय । शुरू में हमारी जो योजनायें बनी हैं, भारत की जन-शक्ति के विरोधाभास और पूरी स्थिति उसमें झांकती हुई नजर आती है । भारतवर्ष में बेरोजगारों की समस्या जटिल से जटिलतर और जटिलतम होती जा रही है । बेरोजगारी को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि काम करने वाले इच्छुक एवं शारीरिक रूप से तत्पर नौजवान को वर्तमान परिस्थितियों में काम करने का अवसर आज के पारिश्रमिक रेट के अनुसार नहीं मिल पाता है । भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार इस समस्या पर विचार प्रकट किये हैं । देश के सारे नौजवान जो काम नहीं कर रहें हैं उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है । कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौजवान तो हैं पर शारीरिक रूप से तन्दुरुस्त नहीं है । कुछ ऐसे लोग भी है जो तन्दुरुस्त तो हैं पर काम नहीं करना चाहते है । राष्ट्रीय आय जो है उसके वे भागीदार बनना चाहते हैं । इस प्रकार के लोगों को हम बाहर रखकर आज विचार करेंगे । जो नेशनल इनकम में बिना काम के, बिना श्रम के, बिना व्यक्तित्व के, हिस्सा चाहते है, उनको अलग रखकर सोचते हैं तो लगता है कि देश के बेरोजगारों की तुलना में रोजगार के अवसरों में लगातार कमी होने के कारण यह समस्या विकराल राक्षस का रूप लेती जा रही और इसका प्रमुख कारण तीव्र गति से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है । जब कि हम किसी समस्या के कारण की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, उसको जड़ से उखाड़ फैंकने की कोशिश नहीं करेंगे उस समय तक उस समस्या का समाधान कागजों पर और भाषणों में और प्रस्तावों में और आंकड़ों में ढूंढते रहेंगे । चाहे सरकार लाख प्रयत्न करे, सब के लिए रोजगार जुटा पाना असंभव है जब कि जनसंख्या और बेरोजगारों में पैरलल मुकाबला चल रहा है । मुकाबला में जनसंख्या की दौड़ काफी तेज है । मैं इसकी पुष्टि भूतकाल के आंकड़ों से करना चाहता हूं । वर्ष 1984-85 में रोजगार दफ्तरों के जरिये बेरोजगारों को रोजगार देने में केवल 1.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हो सकी । 1984-85 में पहली जलाई में रोजगार दफ्तरों में 79 लाख से अधिक मैट्रीकूलेट, बी०ए० और एम०ए० पास बेरोजगारों के नाम दर्ज थे । मतलब यह है कि इस तारीख तक बेरोजगारों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 1985 से लेकर 1988 वि 50 प्रतिशत वृद्धि हो गई इसका मूल कारण हम यह मानते है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है । जब श्री संजय गांधी के परिवार नियोजन के कार्यक्रम की बात चली थी तो सारे लोगों ने उसका विरोध किया और उसका इस तरह से विरोध किया कि हमको सत्ता से बाहर आना पड़ा और तीन वर्ष के लिए हम बाहर रहे । जब तक परिवार नियोजन नहीं होगा और परिवार नियोजन तब होगा जब हम दो और तीन बच्चे, बस या आजकल जो एक विज्ञापन आता है, नौजवान शादी करता है तो उसको किन-किन चीजों का उपयोग करने से बच्चे नहीं पैदा होंगे । ये सब चीजे तो हैं ? लेकिन आज एजूकेशन की भी कमी है में इतनी अशिक्षा, इतनी रूढ़ि, इतनी दय, नीयत फैली हुई है गावों में, देहातों चे स्लम एरियाज में, गरीबी की रेखा से नीर जिन्दा रहने वालों में कि दिन भा श्रम और परिश्रम करने के बाद उनका एक ही रिक्रियेशन है और उस रिक्रियेशन का परिणाम है, उस मनोरजन का परिणाम है कि लगातार संतानें उत्पन्न होती है और बड़ी संख्या में होती जाती है । इस पर नियंत्रण लगाना आवश्यक हो गया है । इसके लिये रिस्क लेना होगा । रिस्क जिसको मै कह रहा हूं वह यह है कि परिवार नियोजन होना चाहिये । लेकिन इस परिवार नियोजन के नाम पर मिनिस्टर लोग अपना कोटा पूरा करने के लिये, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं कि जिन लोगों का परिवार नियोजन हो चुका था, जिनकी एक संतान भी नहीं है उनको पकड़ पकड़ कर बधिया कर दिया और पुत्र तथा पुत्री की लालसा उनके मन में सिमट कर रह गई क्योंकि वे विवश थे और इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार अनाचार किया गया । हमारे माननीय दुबे जी समाजसेवी है । आप हमारा संदेश कैबिनेट में रखे कि अगर इस चीज को शुरू करना है अगर आप चाहते हैं कि परिवार नियोजन हो तो इसको

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

कैबिनट में ही शुरु कराइये । दो या तीन से अधिक जिसके बच्चे हैं उसको मंत्रिमडल से बाहर कीजिए ।

श्रम मंत्री (श्री बिदेश्वरी दुबे) : हमारा एक ही है ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : केवल केन्द्रीय मंत्रिमंडल में नहीं बल्कि कानून बना कर...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): जिनके हो गये, हो गए । आगे के लिये कहें ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : बल्कि कानून बनाकर मेरा आशय है कि चाहे वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल में हो विधान सभाओं में हों चाहे राज्य सभी में हो, उन प्रतिनिधित्व करने वाले लोग पहले अपने ऊपर नियंत्रण करें और परिवार नियोजन के बारे में लम्बी चौड़ी स्पीच टेलीविजन पर विज्ञापित करने से पहले खुद अपने दिल में पहले झांककर देखें । वे अगर इस काम को अपने से चालू करेंगे तो सारे देश में परिवार नियोजन की क्रांति फैलेगी और उसका परिणाम अच्छा होगा । मुझ विश्वास है कि हमारी भावनाओं को, इस सदन की भावनाओं को माननीय दुबे जी कैबिनेट में रखेंगे और उस पर विचार करेंगे । राजीव गांधी की अध्यक्षता में अगर परिवार नियोजन को सफल करना है और बेरोजगारी को दूर करना है तो बिना परिवार नियोजन के बेरोजगारी दूर नहीं होगी गुणात्मक संख्या में दो है तो चार और चार से सोलह और फिर सोलह को सोलह से गुणा कीजिये वह इतनी तेजी से बढ़ती है इसको आप इस तरह रोक नहीं सकते । जिन देशों ने उन्नति की है, चाहे आप किसी भी देश को ले लीजिये उन्होंने अपने देश के बेरोजगारों को रोजगार देकर, उनको काम में लगाकर की है उन्होंने उनके श्रम को उनकी निष्ठा को, उनकी भावनाओं को उनके समर्पण और उनके डिवोशन को आप तभी ले सकते हैं जब उनका पेट भरा हो । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता है । श्री जोगी जी मध्य प्रदेश के है और मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े समाजसेवी, साहित्यकार, कवि और पत्रकार माखन लाल चतुर्वेदी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है । आज सबेरे कम्युनिकेशन सेंटर में उनके शताब्दी समारोह का मैंने उद्घाटन किया । वे इतने बड़े आदमी थे जिनके बारे में महात्मा गांधी जी ने भी लिखा है कि मैं तो इसलिये माखनलाल चतुर्वेदी के गांव जाता हूं क्योंकि उनकी तरह बोलने वाला और क्रांतिकारी विचार रखने वाला मेरी निगाह में दूसरा हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों में नहीं दिखाई पड़ता । उस कवि ने 1954 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर "प्राण का श्रृंगार" शीर्षक से एक कविता लिखी थी । इस बेरोजगारी की समस्या का उस पर प्रकाश पड़ता है, उससे संबद्ध है । इसलिये इस कविता की कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

वाणि वीणा और वेणी की त्रिवेणी धार बोले,
नृत्य बोले, गीत बोले, मूर्ति बोले, प्यार बोले ।
आज हिमगिरि की पुकारों, सिन्धु सौ-सौ बार
बोले,

आज गंगा की लहर में, प्रलय का व्यापार बोले ।
युग तरुण, तव, नेह तक, वह नेह का नव-
ज्वार आया,

काल की हुंकार आयो, प्राण का श्रृंगार आया ।
कोटि-शिर ये शिर नहीं, बलि के अनन्त
प्रसाद हैं ये,

और काली के चरण के मधुर नूपुर-नाद हैं ये केवल शिर नहीं है बलिदान कर ने वालों का किला नौजवान बन गया था इस देश में दें ।

तीर्थ ? ये ऊंचे उठायें शिर, गगन से बोल-बोलें,
सांस लेती लाश को नीचे गिरा—जिन्दा टटोलें ।

आज ब्रह्मा के स्वरों में, एशिया के द्वार हर्षित,
मित्र के उल्लास हर्षित, शत्रु के संहार हर्षित ।

तीन बाजू से घिरा, यह तरल पारा बार हर्षित
आज दिल्ली के स्वरों ईमान का संसार हर्षित ।

देख जन-गण-मन कलंकित कर न दे आकाशवाणी,
क्यों कहे विजयी तिरंगा विश्व-शोषण की कहानी
आकाशवाणी रेडियो से नहीं देववाणी से है ।

आज तेरे नेह पर, असहाय का अभिमान ठहरा
दीन का ईमान ठहरा, पीड़ितों का मान ठहरा ।

चरणतल में भूमि ठहरी, शीष पर भगवान ठहरा।
एक अंगुली के इशारे अखिल हिन्दुस्तान ठहरा।

बेच मत देना जवानी, बेच मत देना हुशारे।
बेच मत देना किसी को, ऐ सुधी, सपने हमारे।

इतनी शौर्यमयी वाणी कवि ने कही है कि –

विश्व की हाटों हमारे प्राण का नीलाम मत हो और उनके स्वार्थ पर जग में कठिन संग्राम मत हो
रक्त से मीठे सलोने आज श्रम-सीकर, न जाने। लो उठो, गाओ, घिरो, छाओ, रचो बहिन सुहाने।

गणतंत्र दिवस, 1954 में यह युगचरण कविता लिखी गई थी जिसमें स्पष्ट कहा गया कि बेच मत देना जवानी, बेच मत देना हुशारे, बेच मत देना किसी को, ऐ सुधी, सपने हमारे। सन् 1947 में हम स्वतंत्र हुए और 40 वर्षों के बाद हमारे नौजवानों के सपने बेच दिये गये। उनकी प्रगति की ओर जो इशारा था जिसमें

हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती।

यह शंखनाद करने वाले नौजवानों के सपने बिक गये। इशारा जो उनकी प्रगति का था वह अवरुद्ध हो गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे मंत्रियों को जानता हूं चाहे वे कोआप्रेटिव विभाग के हों या किसी दूसरे विभाग के हों जब चपरासी की जगह निकलती है तो उनके एजेंट छूट जाते हैं। न एप्लीकेशन देखी जाती है न कुछ देखा जाता है 10 हजार, 20 हजार रेट बंधा हुआ है रेट लेकर इम्पलायमेंट देने वाले जो मिनिस्टर हैं या अधिकारी हैं उनको खुले आम जमीन में खन कर गाड़ देना चाहिये।

श्री विश्वेश्वरी दुबे: उपसभाध्यक्ष जी, ऐसे जनरल आक्षेप नहीं करना चाहिये। यह अनुचित होगा।

THE VICE-CHAIRMAN SHRI JAGESH DESAI): He is not talking of any particular Minister. He is talking only...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : जरूरत पड़ी तो मैं उन लड़कों की भीड़ आपके बंगले में लगा दूंगा दुबे जी, मैं आपसे कम सरकार का खैरख्वाह नहीं हूं लेकिन सत्य कहने पर नियन्त्रण मत लगाइये। लिया जाता है, खुले आम लिया जाता है। इम्पलायमेंट एक्सचेंज के दफ्तरों में नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए पैसा लिया जाता है, नाम भिजवाने के लिए पैसा लिया जाता है। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। हम सब सरकार के वफादार लोग बैठे हैं लेकिन जो सत्ता के दलाल सत्ता में घुस गये हैं जो राजीव गांधी के सपनों को चकनाचूर करना चाहते हैं और नौजवानों को उनकी रोजी रोटी में घूस ले कर, नौकरियां देना चाहते हैं उनको जमीन में खन कर गाड़ना होगा और कृत्तों से उनका सर नुचवाना होगा तब इस देश में न्याय होगा और बेकारी की समस्या दूर होगी। चाहे कांग्रेस का मिनिस्टर हो या किसी और दल का मिनिस्टर हो। हर जगह भ्रष्टाचार है उससे आप इन्कार नहीं कर सकते है। मैं सामूहिकता की बात नहीं कर रहा हूं समूहिकता में अधिकांश परसेंटेज पवित्र लोग है अगर दूध के गिलास में एक बूंद नीबू डाल दिया जाए तो सारा दूध फट जाएगा। ऐसे तत्वों को अलग करना पड़ेगा तब राजीव गांधी का समाजवाद चलेगा तब राजीव गांधी जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को जो रोजगार देना चाहते है वह सपना पूरा हो जाएगा। मेरा जो संकेत था उसको मंत्री जी ने कुछ और समझ लिया कि मैं सामूहिक रूप से कह रहा हूं। मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी इसी समस्या से चिन्तित है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या भारत समेत अन्य अविकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों को भी अपनी चपेट में ले रखा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के निर्देशक राबर्ट फल्जी के अनुसार विश्व में बेरोजगारी की संख्या 12.5 करोड़ है। इनमें 5.5 करोड़ अविकसित देश के हैं भारत में लगभग 2.5 करोड़ बेरोजगार हैं जो विश्व का लगभग 20 प्रतिशत है।

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के सांख्यिकीय विभाग ने रोजगार से संबंधित सन् 2000 तक के आंकड़ों का जो तखमीना लगाया है वह है बेरोजगार 5 करोड़, अल्प रोजगार 30 करोड़ और नये रोजगारों के लिए 125 करोड़ । इनमें विकासशील देशों के आंकड़े 106 करोड़ भी शामिल है । यह ठटस्थ अवैयक्तिक आंकड़े समस्त विश्व की एक ज्वलंत मानव समस्या बने हुए हैं। ये आंकड़े तो चौंका देने वाले है किन्तु अल्प रोजगार और छिपी बेरोजगारी की पूरी तस्वीर वे पेश नहीं करते हैं क्योंकि ये आंकड़े काम पाने के गर्जमन्द उन्हीं लोगों के है जो राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं मे पंजीकृत है । इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अल्प रोजगार की समस्या का मूल्यांकन किया गया है और विकासशील दशों में अधिसंख्य कामों से इतनी मामूली आमदनी होती है कि एक गरीब कामगार परिवार की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं । भारत बेरोजगारी की क्षतिपूर्ति के प्रावधान मे भी प्रयोग कर रहा है। जो सख्त रोजगार हैं, वे बरकरार हैं । लोग अपनी मनपसंद के काम ढूढना चाहते हैं। कम समय में काम पाना चाहते हैं, कोई न कोई रोजगार जल्दी से मिले यह लोगों का प्रयत्न होता है लेकिन वे अपना मन उसमें नहीं मिला पाते है । आज अन्य देशों की तुलना में भारत में उच्च शैक्षणिक योग्यताओं के लिहाज से रोजी मिलना ज्यादा दुष्कर होता जा रहा है। स्नातक और पी०एच०डी० लोग भी क्लर्की और चपरासी का काम करने के लिए पहुंच जाते है। कहते है हमको काम दिलवाइये चाहे चपरासी का काम करना पडे । नौजवान कहता है दूधमूहां मैं नहीं हूं, बच्चे पैदा हो गये हैं उनके दूध के लिए पैसा नहीं है । आपके पास भी मान्यवर, उपसभाध्यक्ष जी आते होंगे, माननीय मंत्री जी के पास आते होंगे । हर जनसेवक के पास आते हैं और कुछ हम कर नहीं पाते हैं ।

हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? शिक्षा का उद्देश्य तो प्रतिभा के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करके योग्यतानुसार समाज में प्रतिस्पर्धा के सा अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना है । हम वही मैकाले की शिक्षा नीति चला रहे है । मैकाले ने कहा था हम क्लर्की खोलने के कारखाने स्थापित कर रहे हैं । घंटी बजती है अध्यापक क्लास में जाता है, मजदूर कारखाने में जाता है, घंटी जब बंद होती है तो मजदूर प्रोडक्शन करके देता है लेकिन अध्यापक क्या देता है, एक भीड़ पढे लिखे लोगों की जो अपनी शिक्षा के अनुरूप काम नहीं पाते हैं और वे एक विचित्र मानसिक पीड़ा और संत्रास से ग्रसित हो जाते है । स्नातक लोगों में बहुतेरे ऐसे हैं जो 50 रुपये से डेढ़ सौ रुपये तक की नौकरी की लालच में घूम रहे है कि कुछ तो मिल जाये, बच्चे को दूध तो हम पिला सकें जो नयी नयी सन्तान 6 महीने की मेरे पास है । आज अभिभावक माध्यमिक स्तर की शिक्षा दिलाने के बाद बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाने की ओर अधिक ध्यान देने लग हैं जिससे कि जीवनयापन के संसाधन जुटाने में वे सक्षम हो सकें । 1985 में मार्च में रोजगार मांगने वालों का अनुपात संगठित क्षेत्रों में रोजगार याफ्ता लोगो से 60 फीसदी ज्यादा था । यह अनुपात तेजी से बढ़ता जा रहा है । यह ध्यान देने की बात है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि की दर 3.8 प्रतिशत तक पहुंची थी जबकि निजी क्षेत्रों में यह दर सिर्फ 2.3 फीसदी पर अटक गयी है । इस प्रकार बढ़ती हुई बेरोजगारी, रोजगार के अपेक्षाकृत कम मौके, संगठित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को रोजगार न दे पाने की हालत, भारतीय अर्थव्यवस्था की लगातार खस्ता हालत और उसपर मंडराते जबदस्त खतरे, ये सब हर चिंतक, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं । देश की तमाम नयी पुरानी समस्याओं में बेरोजगारी पर काफी चर्चा हुई है और बराबर होती रही है । पर समस्या सुलझाने के बजाये उलझती ही जा रही है । इस समस्या की पृष्ठभूमि में कई छोटी बड़ी समस्याएं हैं जिनके मूल में शिक्षा नीति और हमारी विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि है जिससे बेरोज-

बारी बढ़ रही है। पंद्रह वर्ष पहले बेकारी, अर्ध-बेकारी पर विचार करने वाले राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कहा था कि अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी जन-शक्ति की विरोधाभासपूर्ण स्थिति उत्पन्न है। कतिपय वर्ग के क्षेत्रों में जन-शक्ति की कमी है, तथा वही बहुतायत है। इस प्रकार जन-संख्या वृद्धि और आयोजन कार्यक्रमों को चालू करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुकूल कामयाबी न मिलने के कारण बेकारी मिटने की बजाए बढ़ती जा रही है।

3 P.M.

देश में व्यापक जन असंतोष तथा खास करके युवा वर्ग के असंतोष का मूल कारण भी यही है। अतः बेकारी की स्थिति का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने के लिए रोजगार की व्यापक परिभाषा निर्धारित करने की तीव्र आवश्यकता है। तभी जन शक्ति का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में सुनिश्चित कार्यक्रमों के साथ हो सकेगा। शिक्षितों की बेकारी मिटाने के लिए सृजनात्मक रूप से सुगठित, संतुलित प्रयास करना आवश्यक है।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के सिलसिले में दिल्ली प्रशासन ने एक सोसाइटी बनाई है। यह सोसाइटी मुफ्त में प्रशिक्षण दिला कर जो लाभप्रद व्यवसाय खोलना चाहते हैं अपने श्रम से, उन शिक्षित बेरोजगारों की मदद करती है। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस तरह की जो सोसाइटी है, वह सारे देश में विभिन्न स्थानों में खोली जाए और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस मद में दिल्ली में 50 लाख रुपया आवंटित किया गया था। इस तरह की सोसाइटी और राज्यों में भी खोली जाएं। दिल्ली में जो योजना शुरू हुई है, वह सारे देश में लागू हो, तो लोग स्वयं अपने हाथों से निर्माण करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है और निर्भीक होकर जो दिल में है –

इश्क को दिल में दे जगह ग़ालिब,
शायरी इल्म से नहीं आती।

दिमाग में कुछ, दिल में कुछ, ज़बान पर कुछ, यह न करके जो सच्चाई है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी नेशनल रूरल इम्पलायमेंट प्रोग्राम चलता है, रूरल लैंडलैस इम्पलायमेंट जेनरेशन प्रोग्राम चलता है, ट्रेनिंग फार यूथ सेल्फ इम्पलायमेंट चलता है स्पेशल ट्रेनिंग एंड इम्पलायमेंट फार अर्बन पुअर चलता है, स्पेशल इम्पलायमेंट फार अर्बन सेल्फ इम्पलायमेंट फार एजुकेटिड एण्ड अन एजुकेटिड यूथ – यह सब हमारी योजनाएं जो राजीव गांधी की सरकार ने बनाई हैं और कोशिश की है कि गांव से लेकर के शहरों तक में जो बेरोजगार हैं, उन्हें अधिक से अधिक संख्या में हम रोजगार दे सकें।

इस वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री, माननीय चव्हाण जी ने नेहरू जी की सौवीं जयन्ती के उपलक्ष्य में कहा है कि हम नेहरू रोजगार योजना संचालित करेंगे और इस योजना के तहत उन्होंने जो कार्यक्रम निर्धारित किये हैं, उसका मूल लक्ष्य है कि इस योजना में पांच अरब की व्यवस्था की गई है और इसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाए ताकि वह अपनी योग्यता अनुरूप लाभ उठा सके। यह रुपया हम किनसे ले रहे है ? उन लोगों से ले रहे हैं, जो बहुत अधिक धन होने से परेशान हैं कि वहां खर्च करें, क्या करें, जो पैरेलल इकानमी चला रहे हैं, उन लोगों पर हम टैक्स लगा करके ले रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि राजीव गांधी की सरकार का यह काम एक क्रांतिकारी काम है।

सरकार को पूरी प्रादेशिक सरकारों को वित्तीय और दूसरी तकनीकी सहायता देनी चाहिए ताकि प्रादेशिक सरकारें अपने अपने राज्यों में तकनीकी संस्थायें खोले और लोगों को दस्तकारी और घरेलू उद्योग में पर्याप्त जानकारी और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों को

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

भी निर्देश देना चाहिए कि ऐसे युवकों को अपने उद्योग लगाने के लिए उचित वित्तीय सहायता प्रदान करें। ग्रामीण निधनों के लिए रोजगार पदा करने वाले जो कार्यक्रम हैं, वह बड़े ही सराहनीय और प्रशंसनीय है, लेकिन फिर मैं उसी बात पर आना चाहता हूं कि जिनके लिए हम कर रहे हैं, उन तक सहायता पहुंचती नहीं है। अगर कोई भैंस के लिए अनुदान ले लेगा तीन हजार रुपया, तो उसके ऊपर बीस नोटिस जायगी क्लेक्टरेट के मातहत अधिकारियों की लेकिन जो करोड़ों लाखों रुपया पचाए हुए हैं जो कि देश के नौजवानों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए हैं, उनको हमें बेनकाब करना होगा। माननीय उप सभाध्यक्ष जी, यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम दृढ़ निश्चय न कर लें कि हमको यह करना है। आपने जमीन पर सीलिंग लगाई है कि 18 एकड़ से अधिक कोई जमीन नहीं रख सकता है। आज भारत के तीन सौ करोड़ जो एजिस्टर्ड नहीं हैं उनकी संख्या और भी ज्यादा है, बेरोजगारों को स्व-रोजगार दे सकते हैं। कैसे? जो पैरलल इकोनोमी ला रहे हैं समाज में तस्कर, अफीम बेचने वाले हैं। वे ऐसी चीजें बार्डर से लाते है जो कि बैन हैं। हमारे देश के चारों तरफ यह काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। वे सफेदपोश बन करके समाज में इज्जत के अधिकारी बने हुए हैं और उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है। वे जन सेवा के क्षेत्र में घुस गए हैं गांधी जी के सफेद कपड़ों को पहन करके जिस तरह से समाज का शोषण वे कर रहे हैं वह सब कैसे रुकेगा, इस पर हमें सोचने की जरूरत है? बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उद्योगों मे हड़ताल हो जाती है, फिर तालाबंदी हो जाती है और मिलें बंद कर दी जाती हैं। दत्ता सामंत ने बम्बई में मिल मजदूरों का बड़ा भारी आन्दोलन कराया। दुबे जी के प्रदेश में डालमियां का कारखाना है रोहतास मे वहां पर उप सभाध्यक्ष जी, मैं गया था। लोग रोते हुए जाकर कह रहे थे कि हमको औरतों की अस्मत बिकवा करके पेट भरना पड़ रहा है। दस हजार मजदूर बेकार पड़े हुए हैं और आज वे इस स्थिति में आ गए हैं कि अपना पट भरने के लिए उन्हें अपनी औरतों की इज्जत लुटवानी पड़ रही हैं। उनको कुछ न कुछ काम देना ही चाहिए। चाहे सरकार उन्हें काम दे या पूंजीपति दें, डालमिया दे। उसका सारा ग्रांट बैन कर दिया जाए जो कि वह गवर्नमेंट से सहायता पाता है कि जब तक तुम काम नहीं दोगे तब तक तुम्हें एक पैसा नहीं दिया जायेगा। सरकार यह कड़ाई क्यों नहीं करती? लाखों मजदूरों की जिन्दगी बर्बाद करने का श्रेय मैं दत्ता सामंत को देना चाहता हूं और खुले आम देना चाहता हूं। मिल हड़ताल के नाम पर उन्होंने जो आंदोलन चलाया हो सकता है कि इस देश को तोड़ने वाली ताकतों को उससे मदद मिली हो? इस देश की राष्ट्रीयता में विश्वास करने वाले भूखे इंसानों को कोई मदद नहीं मिल सकती। उप सभाध्यक्ष महोदय, इस देश की जनता निरक्षर हो सकती है, गरीब हो सकती है, फटे-पुराने कपड़े पहनने वाली हो सकती है, एक समय खाना खा करके जिंदा रहने वाली हो सकती है, अपने बच्चों को अशिक्षित रख करके वह जिंदा रह सकती है, लेकिन इस देश की जनता बेईमान नहीं है। राष्ट्रीयता में उसका विश्वास है। बेरोजगारों के लिए जितना अधिक काम इंदिरा गांधी की सरकार ने किया या राजीव गांधी की सरकार कर रही है, जो 1947 के बाद राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं, बहुत से राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं, किसी भी देश में इस तेजी के साथ काम नहीं हुआ है। लेकिन उसकी मोनिटरिंग जो आप योजनाएं चलाते है दिल्ली से और सवेरे भी आपने देखा कि तुरन्त मंत्री जी ने खाद्य मंत्री जी ने कहा कि यह स्टेट सब्जैक्ट है, जबकि मैंने कहा कि मैं यह नहीं सुनना चाहता कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। राशन की दुकान पर आप राशन देते हैं और सैन्टर से कोई मोनिटरिंग नहीं करते हैं। स्टेट में डिस्ट्रिक्टस में तो लूटने वाले हैं और सारा ब्लैक हो जाता है। इसलिए जो योजनाएं हम बनाएं उनका अच्छी तरह से कार्यान्वियन हो, ठीक ढंग से प्रयोग हो और वह प्रयोग तभी हो सकता है जबकि शासन

का भय हो कि अगर हम काम दिए जाने वाले व्यक्ति से घूस लेते हुए पकड़े जायेंगे तो हमारा हाथ काट दिया जायेगा। कानून आपकी श्रम शक्ति है। जो कानून है वे ऐसे उलझे हुए हैं और दुबे जी इनको सरल बनाने के लिए कुछ करें क्योंकि इनका पूरा जीवन मजदूर आंदोलन में बीता है। मुख्य मंत्री रहे हैं और मंत्री तो यह है लेकिन श्रमिक आंदोलन में कांग्रेस के एक सपूत के रूप में इनकी चर्चा सारे देश में होती है, इसीलिए श्रम मंत्रालय का भार आपको दिया गया है। तो ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों को रोजगार मुहैया हो। सब से बड़ करके मैं ग्रामीण निर्धनों के लिए जो आपने रोजगार योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पूर्ण अधिकार दिया है उनको सारी चीजें मिलें। देश भयंकर बेरोजगारी की गिरफ्त में है। आज शौक चढ़ आता है, गांव का पढ़ा-लिखा नौजवान जब देखता है शहर में आकर, तो चकाचौंध में डूब जाता है।

रेस्पेक्टेड वाइस चेयरमेन साहब, मैं पांच-सात मिनिट में खत्म कर दूंगा। मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आप संकेत की भाषा कहते हैं।

जानता हूं प्यार की भाषा अजानी, किंतु
कह सकता नहीं कुछ भी जुबानी।
आज सपनों की भुजा पर टेक कर सिर,
हो गई है साधना की मौन वाणी॥

मान्यवर, बेरोजगारी एक भयंकर गिरफ्त में कसती जा रही है।

वर्ष 1951 में 53 लाख बेरोजगार थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1956 में 56 लाख थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में 90 लाख थे, मार्च 1985 में 2 करोड़ 1 लाख 40 हजार थे और वर्ष 1987 में 3 करोड़ 2 लाख 87 हजार थे। पंजीकरण 60 लाख का हुआ और काम मिला 3 लाख 34 हजार को। मान्यवर यह रेशो बड़ा चिंतनीय है। वर्ष 1961 से 1971 के बीच कृषि उत्पादन बिजली, गैस, जल, व्यापार यातायात, भंडार, संचार सुविधाएं सार्वजनिक और सरकारी प्रतिष्ठानों में निश्चित रूप से रोजगार में वृद्धि हुई है, लेकिन जिस गति से हमारे बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, उससे बहुत कम है। देश में एक सीधी बेरोजगारी होती है और दूसरी जहां व्यक्ति की जरूरत है वहां भी आदमी नहीं मिल रहे। मैं उदाहरण दूं कि हर जगह राजभाषा के लिए हिंदी के टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर चाहिए और लोग कहते हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए दोषी कौन हैं? हमारे जो सेलेक्शन कमीशन हैं बैंकिंग के अलग हैं पब्लिक सर्विस के अलग हैं वहे लोग चाहते ही नहीं कि मिलें। मान्यवर देश में हजारों की संख्या में रोजगार टाइपिस्ट मिल सकते हैं पर स्वयं सरकारी कर्मचारी इस तरह से कसकर रखा है कि लोगों को काम नहीं मिल पाता है।

आपने कम्प्यूटराइजेशन कर दिया जहां दस-दस काम करते थे, वहां केवल एक व्यक्ति टकटक बटन दबाएगा और सब कुछ आ जाएगा, लेकिन उन नं का क्या होगा? हम नकल तो करते हैं विदेशों की, करना भी चाहिए, लेकिन जो उन कामों से खाली होते हैं, उनको भी हमको एब्जार्ब करना होगा। हमारे नेता राजीव गांधी अपने विचारशील क्रांतिकारी विचारों के साथ कुछ करना चाहते हैं। बेरोजगारी के लिए डिग्री से रहित हम शिक्षा देंगे, अगर कोई बढ़ई का काम करता है, उसे एम.ए. करके क्लर्की या चपरासी के लिए घूमने की क्या जरूरत है? अगर कोई बहुत अच्छा चित्रकार है तो उसे क्लर्की के लिए घूमने की क्या जरूरत है? इन उद्योगों और कार्यों को बढ़ाकर हमें बेरोजगार योजना को अधिक से अधिक कार्यान्वित करना होगा और कृषि उद्योग, उच्च टैक्नोलोजी से भी हम इस काम को कर सकते हैं व्यवसाय-मूलक शिक्षा नीति के बदले आज हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, जो केवल जोड़-घटाना या ड्राफ्ट बनाना, यही कर सकती है।

मान्यवर, पुर्तगाल देश की जितनी जनसंख्या है उतने लोग एम्पलायमेंट

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

एक्सचेंज में बेरोजगारी के दरवाजे पर खड़े हैं हमारे देश में। जापान में 1.3 ब्रिटेन में 3.4 संख्या बेरोजगारों की है और अपने यहां इतने अधिक हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। गांधी जी ने इस देश को स्वतंत्र किया जवाहर लाल नेहरू ने माडर्न आर्किटैक्ट के रूप में इस देश को दुनियां का सिरमौर बना दिया। सारी दुनियां गांधी के देश के जवाहर को देखती थी, जब पंचशील के सम्मेलन होते थे या गुट निरपेक्ष के सम्मेलन होते थे। इंदिरा गांधी ने विश्व निरस्त्रीकरण और सारे थर्ड नेशन को एक करके यह दिखा दिया कि जहां शक्ति होगी वहीं सारी ताकत जुड़ेगी। राजीव गांधी एटोमिक अस्त्रों की होड़ को समाप्त करने की ओर बढ़े हुए हैं। अब यह उनके सहयोगियों का काम है कि इस तरह से योजना बनाएं, कार्यान्वित करें ताकि बेरोजगारी मिटे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था को अगर हम छोड़ देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। गांधी जी ने खादी को चेतना का अनावरण बनाया। महोदय, खादी कपड़ा नहीं था, वह हमारी चेतना की प्रतीक था। स्वच्छ चेतना की प्रतीक थी और उस प्रतीक के माध्यम से घर-घर में चरखा कतवाने का काम करके गांधी जी ने क्रांति कर दी। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में देश का नौजवान कूद पड़ा था और तब यह देश स्वतंत्र होकर मस्त अंगड़ाई लेकर झूमकर चल सका। सन् 1920 में जो आंदोलन खड़ा हुआ और देश 27 वर्षों में अपने को स्वतंत्र करा सका। महोदय, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो पढ़े-लिखे नौजवानों के लिए नौकरी देना बंद किया जाना नहीं चाहिए। उनके लिए वितरण की बहुत अच्छी योजनाएं प्लानिंग कमीशन में बैठकर, श्रम मंत्रालय में बैठकर लोग बनाते है लेकिन उसमें से कितनी योजनाओं को हम एक्जीक्यूट कर पाते हैं? उसका सही ढंग से कितना लाभ हम गरीबी रेखा से नीचे जिंदा रहनेवालों को दे पाते हैं? आज राजीव गांधी कहते हैं कि हम केन्द्र से 6 रुपए भेजते हैं लेकिन गरीब तबके तक एक ही रुपया पहुंच पाता है। हम बाढ़ में लोगों की सहायता के लिए सूखे से लोगों की मदद के लिए, बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए भेजते हैं लेकिन वह वेस्ट बंगाल में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बंटता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम के लोग बांटते हैं। वह जनता तक नहीं पहुंच पाता है आज संस्कार खत्म होते जा रहे है। व्यक्त लज्जा, सुखी भवेत। आज तो लोगों ने लज्जा छोड़ दी है भले ही कोई कुछ कहे। आज ऐसे तत्व हर देश में हैं, हर पार्टी में और हर वर्ग में है। हमें ऐसे तत्वों को छांटना होगा। श्री राजीव गांधी ने 28 दिसम्बर, 1985 को बंबई के ऐतिहासिक मैदान में नारा दिया था कि हम सत्ता के दलालों को बेनकाब करेंगे। आज राजीव गांधी जहां रोक रहे हैं उन सत्ता के दलालों को बेनकाब करने से? किस मिनिस्टर को रोका है? डंके के चोट पर हमें सत्ता के दलालों को बेनकाब करना होगा। हम जन प्रतिनिधियों को उस काम को करना होगा। तब जाकर इस बेरोजगारी की समस्या से हम उभर पाएंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सामुदायिक विकास, ग्रामीण रोजगार और एंटी पावर्टी प्रोग्राम में निश्चित रूप से हमें यह देखना है कि इनका लाभ सही आदमी तक पहुंच सके। यह तभी पहुंच सकता है जब आप अचानक चैकिंग करिए कि पहुंचा या नहीं? आप ऐसे लोगों को पकड़िए और इस्तीफा लीजिए, चाहे मिनिस्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे अफसर हो। इस चीज की हमें कड़ाई के साथ लागू करना होगा।

हमारे मित्र भाई जोगी जी ने प्रस्ताव रखा है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। अगर संविधान की तीसरी धारा में यह प्रावधान करना है कि बेरोजगारी को हम दूर करेंगे तो उस पर भी विचार करें और बनाएं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अंत में इस सदन के माननीय सदस्य जो अब हमारे बीच नहीं रहे। वह इंटरनेशनल रिप्यूट के अर्थशास्त्री थे और डिप्लोमेट थे। उन पंडित लक्ष्मीकांत झा ने आर्थिक क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी

है । वह बिहार से संसद सदस्य थे और माननीय हमारे दुबे जी मंत्री जी भी बिहार से है । उनसे एक बार किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपकी निगाह में देश की वे कौनसी प्रमुख समस्याएं हैं जिन पर कि पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है ? उनकी प्रतिभा से आप परिचित हैं । वह बहुत कम बोलते थे लेकिन जब बोलते थे तो साधिकार बोलते थे । उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति को मैं सराहनीय मानता हूं । लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे मदों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं । बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि, इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक है । दुर्भाग्य से बेरोजगारी के संबंध में जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे न तो व्यवस्थित हैं और न ही अधिक विश्वसनीय है । उत्पादन और मूल्य वृद्धि के सूचकांक हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, इसके साथ-साथ उनकी सही गिनती भी नहीं हो पाती । आर्थिक प्रतिस्पर्धा और बेरोजगारी के असंतोष के फलस्वरूप समाज में तनाव बढता है और साम्प्रदायिकता, जातिवाद और आतंकवाद जैसी बुराइयां पनपती हैं । फिर पूछा गया कि समस्या से आप कैसे निपट सकते हैं ? जातिवाद, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद जैसी बुराइयों के मूल में बेरोजगारी है । हर नौजवान चाहता है कि वह पढ़-लिखकर अपने अनुरूप समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करे और अपने को व्यवस्थित कर ले काम करके, मेहनत करके, लेकिन जब वह देखता है कि काम नहीं मिलता है तो बैंकों में डाका डालता है, आतंकवादी बनकर के इस देश की मिट्टी को खून से रंगता है । कैरियर बनकर के तस्करों का सामान बेचता है । जुआ खेलता है, आवारा गर्दी करता है । भ्रष्ट से भ्रष्ट काम करने के लिए, पेट की ज्वाला के कारण, विवश होता है और उसका कारण यही है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए की गई हमारी कोशिशें गलत खामियों का शिकार हुई हैं । हमारी अर्थव्यवस्था की मूलभूत कमियों को दूर करने के लिए कुछ नई योजनाएं प्रस्तावित की जा सकती है । इससे भारी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे । आवास निर्माण एक शक्तिशाली कार्यक्रम है और मूलभूत समस्या से तो छुटकारा पाया ही जा सकता है, इसके साथ-साथ भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं । जो लोग निर्माण के कार्य में लगे हैं उन्हें तो काम मिलेगा ही, इसके अलावा बिल्डिंग मैटिरियल और मकान के लिए दूसरी सहयोगी सामग्री के काम में भी हजारों-लाखों बेरोजगार खप सकते है । हल्के और छोटे उद्योगों में रोजगार के ज्यादा अवसर रहते हैं, इसलिए इन उद्योगों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । मुद्रास्फिति संबंधी दबाव की आशंका के कारण इस क्षेत्र में पूंजी विनियोजन के कार्य में कोई अंकुश लगाना अनुचित है क्योंकि रोजगार बढ़ने के साथ-साथ बाजार में जो अतिरिक्त मांग बढ़ेगी, एक अर्थशास्त्री इस देश का कह रहा है, उसे इन कारखानों से होने वाले अतिरिक्त उत्पादन से पूरा किया जा सकेगा । एक अच्छा सुझाव है, इस पर मुझे विश्वास है कि माननीय दुबे जी का मंत्रालय अवश्य विचार करेगा ।

अंत में, माननीय उपाध्यक्ष जी, इस देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है, इस देश में भुखमरी की समस्या बढ़ सकती है, इस देश में हजारों गांव पानी में बह सकते हैं, इस देश में हैजे से तड़पकर के जान नौजवान दे सकते हैं, लेकिन इस देश के नौजवान ही है जो हमारी सीमाओं पर, जहां बर्फ जम जाती है, वहां भी वह अपने को बैग में लपेटकर के राष्ट्र की रक्षा कर रहा है । वह नौजवान ही है जो मीलों नीचे खानों में उतरकर के सोना निकाल रहा है, भूगर्भ में स्थित रत्नों को निकाल रहा है, उत्पादन कर रहा है मेटेरिलेटक और हमको दुनिया की ताकत बना रहा है नौजवान अपना पसीना गिराना जानता है और जिस देश में नौजवानों के पसीने की कद्र नहीं होती है वह देश अपने आने वाले श्रम-शक्ति के पूंजी का, अगर हमारा नारा श्रमेव जयते है तो श्रमेव जयते तब सार्थक होगा जब समाजवादी आर्थिक व्यवस्था इक्वेलिटी में हमारा विश्वास होना चाहिए, एकरूपता में

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

विश्वास होना चाहिए । कहीं किसी का लड़का बड़ी-बड़ी कारों में चलता हो और कहीं बस का टिकट बनवाने के लिए पैसा उपलब्ध हो, तो यह सब विषमताएं दूर करनी चाहिए।

माननीय-उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझ बोलने का मौका दिया । अंत में एक कविता से कि माखन लाल चतुर्वेदी की भावनाएं क्या है कि जवानी बेरोजगार नहीं रहनी चाहिए, हाथों को काम दीजिए, दिमाग को चिन्तन दीजिए, पेट को रोटी दीजिए । राजीव गांधी ने सपना देखा है कि 2000 बरस आते-आते दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती । तो अपने नौजवानों के विश्वास, उनकी कर्मठता की शपथ खाकर, इस सदन में मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती—हमारे नौजवानों की इच्छा-शक्ति इतनी दृढ़, अडिग और राष्ट्रीयता से भरी हुई है । उसके हाथों को रोजगार देना ही होगा और उस ओर हमारे राजीव जो जिस ढंग से, गतिशील ढंग से कदम बढ़ा रहे हैं, उसको एग्जिक्यूट करने का काम जिन लोगों को दिया गया है, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे मंत्रालय के लोग हों, चाहे कमेटीज के लोग हों, चाहे मंत्री हों, वे काम करके दिखावें। कहीं साधनों की कमी नहीं होने पाएगी। श्रीमन् मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी की कविता सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं। यह उस समय की कविता है जब बंदे मातरम् गाकर हमारे नौजवान फांसी के फंदे पर झूल जाया करते थे । हमारे नौजवानों में आज भी वही परंपरा है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने "जवानी" शीर्षक कविता में लिखा है :

प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है
कि तू विधवा हुई, खो आज पानी?
चल रहीं घड़ियां चले नभ के सितारे,
चल रही नदियां, चले हिम-खंड प्यारे।
चल रही है सांस, फिर तू ठहर जाए?
दो सदी पीछे कि तेरी लहर जाए?
पहन ले नर मुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरू कर ले,
मसि-सा तू पहन बाना आज धानी
प्राण तेरे साथ हैं, उठ री जवानी
द्वार बिल का खोल चल भूडोल कर दें,
एक हिम-गिरि एक सिर का मोल कर दे,
मसल कर अपने इरादों सी उठाकर,
दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे?
रक्त है? या है नसों में क्षुद्र पानी,
जांच कर तू सीस दे-देकर जवानी

भारत के नौजवानों में ताकत है, समग्र भारत के नक्शे मे वे सारी ऊर्जा को सम्मिलित व इकट्ठा कर सकते हैं, सारी शक्ति को समेट सकते हैं जिसके लिए कहा है:

चढ़ा दे स्वातंत्र्य प्रभु पर अमर पानी,
विश्व माने तू जवानी है जवानी,
लाल चहरा है नहीं—फिर लाल किसके?
लहू खून? अरे, कंकाल किसके?
प्रेरणा सायी कि आटा-दाल किसके,
सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके?
वेद की वाणी कि हो आकाश-वाणी,
धूल है जो जग नहीं पायी जवानी?
विश्व है असि का? —नहीं संकल्प का है,
हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है,
फूल गिरते, शूल शिर ऊंचा लिये हैं,
रसों के अधिमान को नीरस किये है,
खून हो जाये न तेरा देख, पानी,
मरण का त्योहार, जीवन की जवानी ।

मान्यवर, इसी कविता के साथ मैं विश्वास करता हूं कि बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा भत्ता और काम देकर लोगों की श्रम शक्ति का मूल्यांकन हमारी सरकार करेगी और जो लोग हमारी श्रम शक्ति का निरादर करके अपनी शक्ति, अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढा रहे है, उन्हें यहां से समाप्त करना होगा. तभी "श्रमेव जयते" का सिद्धान्त सही रूप में सार्थक हो सकेगा ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि लगभग एक घंटे तक आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया । धन्यवाद ।

SHRI DARBARA SINGH (Punjab): Sir, I will not take much time of the House. I have to bring to your notice certain very important facts about

this unemployment problem; What is happening and what is the solution.

Sir, there is not only organised or unorganised labour but there is also a huge labour in the field which is not taken care of. Sir, unemployment is a very serious problem which must be dealt with at all levels. But it is good that the Central Government has taken upon itself the task of removal of poverty. Its first priority is to remove poverty from India. The Central Government can only give financial help to the States. But if the States divert those finances for another purpose and if that financial help does not go to the real person who has to take advantage of that and get himself involved in some sort of employment, then naturally you will find increase in unemployment.

Sir, in this connection, I would like to say that it is not only in India that unemployment has increased but all over the developed countries also it is increasing day by day. The reasons may be different there. Here we have a population of 80 crores. The population of all the Europe is not that much. There are other reasons for unemployment there. Here the reasons are different. Here it is not a case of unemployment, but the background of that unemployment. Why is the Central Government being criticised? In the name of unemployment, some other things are being done. There is no doubt that there is unemployment in the country and we have to deal with this problem effectively and see that poor people get some sort of employment. There are many factors which are responsible for it and I shall deal with them later. What is happening in the Employment Exchanges? The Supreme Court has said in its verdict that when these Employment Exchanges send list of candidates to the Government for employment, those candidates are not taken and people from outside are taken. As Dr. Ratnakar Pandey has said, there is something fishy behind all this. We have to see why candidates recommended by the Employment Exchanges are not taken. This is not my charge; this is what the Supreme Court had to say in one case.

Problem of unemployment is on the rise. There are different reasons for it. This has been on the rise for quite long; it is not suddenly that we we have come to know of it. And now the problem has become very acute. I would give one instance of Punjab. One person named Ashok Ghosh went to Punjab and stayed on there for some time. He said that during Barnala Government, the problem of unemployment had increased further. I personally know that people having connections, people who were terrorists, were sending recommendations for employment of certain number of people. The main difficulty is that whatever party comes in power in place of Congress Party, they always think of the most simple way of getting popular among the people of resorting to such practices. And problem of unemployment is the last thing to be tackled. I am happy to say that we in our Party meeting passed the economic resolution a few days ago, before this Budget was submitted to this august House; I was one of the members there; and we jotted down certain things that should be done. And the first item was that where a whole family is unemployed, at least one member from each such family should be provided with employment, so that he can feed the other members of the family. That is not a small thing. Then the other point was about child welfare. Child plays an important part because he is the future of the nation. A child between the age of 6 and 10 is very sensitive to what happens around and what is told to him. Whatever is taught to him, he takes it to his head. So we have to create a feeling in the children which they will carry forward during the coming years. Because it is the children who will lead the country tomorrow. Now we have to provide some facilities to the children. We can provide some food to them. It is called the mid-day meal scheme. An-

[Shri Darbara Singh]

other thing is that those who are below the poverty line, destitute women, will get free sarees. Similar things we had mentioned in our Resolution. Most of these things have been accepted and these have been reflected in the Budget. I appreciate it. We are thankful to the Prime Minister and the hon. Minister of Finance that they have kept in view the present position and further they have also taken care as to what we should do in the coming years.

Sir, I do not want to go into the figures because figures take us nowhere. It is the remedy which is needed the most. I would like to point out that there are doctors—2,500 in number—who are without any job; there are engineers—5,000 in number—who are without any job and there are educated people in other sections of the society who are without job. It is not only the youth who are unemployed; there are also others who are unemployed. Why is this so? This should be kept in view by the Government. The Government should provide all facilities and amenities to the people in the rural as well as in the urban areas.

There is urgent need to undertake an economic survey. Such a survey has not been done so far. Actually, I could do such a thing in Punjab. People in every hut and every home should be contacted to find out how many people there are in a family, how many of them are educated, how many people in the family are working, what is their movable and immovable property etc. If such a survey is undertaken, the Government would be in a position to know the status of each family. On that basis, we can come out with a plan. If we find that in a family nobody is employed, we should provide employment to at least one person in that family in terms of the Resolution which the AICC had passed and which has been accepted by the Government. This is one thing which should be done immediately.

Then, a vast area of wasteland is there in our country. What is being done about it? This can be made use of. People can grow something on in the market and get something for in the market and get something for their livelihood. What is being done about it? There are thousands and thousands of acres of wasteland. Who are cultivating them? Unknown persons. Unnamed persons. They are called *benami*. The earlier the problem is taken care of the better it is for us. Land in excess of the ceiling should be taken away and distributed among the landless cultivators. Landless cultivators should be given the land first. I reason it out like this. Small landholders or very small landholders are the first people who go to the market to sell their produce because they have to feed their family, pay off their debt and start the work again. Those who hold back their stock are those who are waiting for a suitable time so that they can sell their produce at a very high price. These are the people with big landholdings. The Government should keep this in mind. These big landholders are after power, political power, social power, economic power. They want to be the masters of the situation at the cost of the poor peasants who work for their employment, who want to feed their bellies. There can be a remedy for this. There should be a passbook given to every agriculturist. In that, description of his whole land should be given, there should be *khasra* number, total land and it should be attested by the Tehsildar or any other officer appointed for that purpose. On oath he should declare that this is all his land and immovable property.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): In Maharashtra we have got the passbook system.

SHRI DARBARA SINGH: If it is there, it is good but it should be done throughout India. India is a big country with the largest population. It is

faced with a large number of problems. This is the way in which something can be done for those who are have-nots.

Similarly, if he goes to a bank for getting credit, he should not seek assistance from anybody else. He can show this passbook. This is a document granted by the Government. On the basis of this book he should get the credit. What is happening now a days? The poor man goes to the bank but he does not get the credit. He is asked to come again and again, and whatever he gets from the bank half of that is spent on coming and going from one place to the other. He also has to grease the palm of a person who is at the helm of affairs for granting credit. I am sorry, the great lady is no more here, she was assassinated, that great lady, Indira Gandhi, nationalised the banks, but who are the persons working in those nationalised banks They are enjoying the benefits of nationalisation. They do not give full money to the person, they extract something out of that. The poor man has to pay back the credit in a number of instalments, but what will he do with the half or three-fourths of the total money that he gets? So, the working of the national banks should be properly monitored. With what speed they are working, what they have done, how they are disposing of the credit applications, all that should be taken note of and at the time of giving promotions or incentives these things should be taken into consideration. The Government of India has done a very remarkable thing by taking 120 district for employment planning. There is 8 per cent surcharge on those who can pay. I am of the view that those people who have enough money should be asked to pay still more. In Economics there are three things. One is the bare necessities of life. The second is, comforts. We are for bare necessities of life which should be made available to the poor. I am not talking of the comforts for them. There are people who are spending crores of rupees on their comforts. These people have kept the money away from the eyes of the Government and they spend it on luxuries, they spend it on unnecessary purposes for keeping themselves over and above the status of other people. They want to keep the people under their thumb. They also infiltrate with that money into the Governments and make the Governments feel that they are the masters. That can be done if some money is withdrawn from them and given to these people who are poor.

So this is one of the best things done and in due course of time, other things will be taken into account for this purpose. There is the Nehru Rozgar Yojana. I am happy that Pt. Nehru's name is there. It must be properly distributed; it must be equitably distributed to the poor people He was a great statesman; he was not a politician only. He was one of the biggest statesmen in the world who had brought democracy in India and who wanted that the poor should be served first. This was his principle and he did his best during his lifetime. I know much about him. This is not the time to explain it here. Time will come when I will explain who was Nehru and what he had done, who was Indira Gandhi and what she did. All this is to be brought to the notice of the poor people living in villages, in the streets and in the huts. If we bring to the notice of these people what they have done for the country, it can also give them mental relief at least.

Unless the Government does one thing, this equitable distribution will not be there. The public distribution system should be expanded in India. Not that it should be kept to the big cities and towns. That will not serve the purpose. Eighty per cent of the people live in villages. Are those people who are under the poverty line getting the things at the rate which is fixed by the Government? Not at all. Either they do not get them at

[Shri Darbara Singh]

all, or if they get them they get them at very exhorbitant rates, knowing nothing about what is happening in the Government. That must be brought to their notice. It is the duty of the Members of Parliament to take notice of this and to bring it to the notice of the people. It should be done all over India and the State Governments must be asked. Although the States will not approve of this method, but they should be asked to come forward with equitable distribution for these people who are under the poverty line.

I always plead—it may not come soon—that every facility should be on economic basis, not on the reservation basis. Although we have reserved for scheduled castes and scheduled tribes, yet there are other sections of the society who are equally poor but they are not given anything by the Government because they are not covered under that. I am for economic emancipation, and not for particular conditional things. That is a vast subject; it can be discussed later on; but it should be done.

Regarding technology, what is happening today? We came to politics when technology was not there at all. We were going on foot, knocking at the door of each person. There were no roads and whether it was rain or shine, we had to go on food. In this scientific age when all the facilities are available, why can we not contact every hearth and home for making them feel that we stand for them, Parliament stands for them.

In the public sector, there are many loopholes. It must be strengthened. In the last six months, it has made profits. There is no doubt about that. But it needs further strengthening because of the fact that it had been losing previously. Either the management is wrong, or the man at the head of the management is wrong, or the employees and others who are working under him are not efficient. This must be looked into and manitored properly and if it is found that the man cannot manage, the man at the highest post there is in the wrong and not doing well—how is it that all these private companies are having profits whereas there is no profit here? —then he must be asked to go home rather than keep him and go on losing the finances which we draw from the pockets of the people. It should be a profitable public sector and not a losing public sector. The private sector people are enjoying all the best whereas this is the condition of the public sector. Here the employees have a much better say. They have all the rights. One right that has been given to them is that they can also participate in the management, the level at which decisions are taken They are expressing their opinion there and their opinion is, more or less accepted.

Then, the science graduates who are leaving the country must be stopped and work should be given to them here. They have done well wherever they are. The people who have gone from India, have done wonderful work for other countries. They should be taken back and those people who are here should also be employed for the welfare of the country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): May I have the leave of the House to request Shrimati Asima Chatterjee to take the Chair for some time?

SOME HONOURABLE MEMBERS: Yes.

[**The Vice-Chairman Prof. (Mrs.) Asima Chatterjee**] in the Chair.

SHRI DARBARA SINGH: There are two schemes which have been formulated by the Government—IRDP and RLEGP. There are two such other things which are working all right in the field. For the IRDP the Government was giving 100 per cent. For another scheme it was giving 75

per cent. I know of a State—where have been for one month—where they went with the party flag to the panchayats and distributed the whole of the IRDP money to their cadres and none else. This is the plight of the poor people. It was meant for the poor people but it went to the party cadre. If such a thing happens in the States, we have to take care of it. We have given ample rights and responsibilities to the States, and if the rights are so much vitiated by these people, then we have to take care to see that such a thing does not happen. As the Prime Minister has rightly said, there is a layer system which does not allow the whole of the money—financial help—to go to the poor. Out of five rupees only one rupee goes to the person concerned, the beneficiary. Where do the remaining four rupees go? The layer system at the district and State level does not allow these four rupees to go to the person who is concerned, who is poor, who is to be helped, who is to be employed. So, this should be monitored by the Central Government. The Central Government does not come in he way of distribution, but it must do the monitoring because, if monitoring is not done then the poor man will not get any benefit out of these schemes.

Madam, I have said a few things. Much can be said on this topic, but I don't want to take the time of other Members. I think the steps taken by the Government so far are very good, but we must have a very deep view of the Employment Exchanges and see how many people are unemployed and where these people could be accommodated. There should be a good survey of all these so that we also have a good idea of this, because here the figures given by the States are given in their own way. Much more unemployment is there in West Bengal. The Communist Party must be much more concerned about the poor. But very much unemployment is there. It has increased, not decreased. Anyhow, I can mention other States also. I am not going to mention it here only for this purpose. I am saying only this much. Let there be Government monitoring of the money given by the Centre. It is most needed. Crores and crores of rupees are being given from he Centre. I am happy that the purpose that the Government is not doing for the poor. When we give it for the poor, its distribution is improperly done by the States. We should take care of that. Money goes from the Centre. I am happy that the Government, the Planning Commission gave whatever the States wanted. Whatever allocation was asked for for this year, it was given; the same figure was given to them. We would like to see that the money is properly utilised for the uplift of the have-nots, not of the haves.

With these remarks, Madam, thank you very much.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार मानता हूं कि इस महत्वपूर्ण संकल्प पर जो अजीत जोगी ने यहां पेश किया है। देश की आर्थिक व्यवस्था से गहरा संबंध रखता है, उस पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है।

मैं स्वयं इस बात को मानने वाला हूं कि प्रश्न काल और गैर-सरकारी प्रस्ताव के दिन ज्यादा से ज्यादा मेम्बर बोल सकें ताकि ज्यादा सुझाव आ सकें। इसलिए मैं स्वयं उस परिपाटी को मानता हूं और मुझे आज हमारे देशभक्त क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आजाद की श्रद्धांजलि सभा में भी जाना है।

देश की बेरोजगारी का सवाल एक राष्ट्रीय सवाल है, जिस पर सभी लोगों को समान चिंता है मैं अपने पूर्ववक्ताओं, सब से अपने को सम्बद्ध तो करता हूं और उनका समर्थन करता हूं। जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये, एक से एक अमूल्य सुझाव थे। मैं भी दो-तीन बातें संक्षेप में कहना चाहता हूं।

दुनिया में दो ही तरीके हैं बेकारी को दूर करने के लिए, एक तो यह रास्ता है कि

[श्री राम चन्द्र विकल]

जो कम्यूनिस्ट देश हैं, व्यक्तिगत सम्पत्ति ही न हो, सारी सरकार की हो, दूसरा यह है कि हम अधिकारों की बजाए कर्तव्य-परायण हों, हम कर्तव्य को ज्यादा महत्व देते हैं। रूस ने बहुत थोड़े से अभी गोर्बाचोव के आने पर ढील दी गई है, उन्होंने यूनियनों को मान्यता दी है, जो पहले नहीं थी और चुनाव पद्धति में भी उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है। साथ ही दो देश नहीं, बल्कि तीन चार देश ऐसे कहे जाते हैं कि जिनमें कम्युनिज्म नहीं है, व्यक्तिगत सम्पत्ति या अधिकार है काम करने का—जापान, अमरीका और कैनेडा। कैनेडा में बहुत बड़ी जमीन है, पर हो सकता है कि जो हमारे बच्चे जाते हैं कैनेडा में—अच्छी बात है कि जाते हैं और अमरीका जाकर मालदार हो जाते हैं। क्यों वह वहां जाते हैं, यह कारण तो बहुत लम्बे है, उनमें नहीं जाना चाहता हूं। पर जापान का उदाहरण तो मैं जानता हूं और उस पर मेरा बहुत विश्वास भी है। वहां के जो नौजवान हैं उनको कर्तव्य पालन की तरफ अधिक ट्रेनिंग दी जाती है। वहां अधिकारों की लड़ाई कम है। मेरे देश में दुर्भाग्य है कि हम कर्तव्य-परायण की तरफ नौजवानों को कहने के लिए तैयार नहीं हैं और राजनीतिक सलोगन जो लम्बा लगा दे, जो अधिक बात वह दे अधिकारों और अधिकारों की, कर्तव्य की नहीं, हम वोट के लोभ से अधिकार ही अधिकार चिल्ला रहे हैं, कर्तव्य की भावना कहने को तैयार नहीं है। यह इस देश की बेकारी की जड़ में है और नौजवानों की बेरोजगारी के लिए भी। जापान में मैंने देखा छोटे बच्चे इतने अनुशासित हैं कि कालेज, स्कूल में या यूनिवर्सिटी मेंजब भी मैं जाता हूं तो वहां भी यह उदाहरण देता हूं कि छोटे बच्चे खाली सड़क को ग्रीन सिगनल, हरी झंडी बगैर पार नहीं करते। यह अनुशासन मैंने स्वयं देखा है। और

4 P.M. यूनिवर्सिटीज में भी, टोक्यो यूनिवर्सिटी में भी मैं गया हूं। यूनिवर्सिटी के बाहर निकल कर बच्चे जो चीजें खायेंगे वह ट्राम में ही डालेंगे, पिकनिक स्पाट पर भी ट्राम में ही डालेंगे गंदी चीजें कहीं इधर-उधर नहीं डालते। वहां ईमानदारी इतनी है कि खोमचे वाले से पैसे देकरके ही सामान लेंगे लेकिन हमारे यहां यूनिवर्सिटी में कोई खोमचे वाला चला जाए तो उसे लूट कर चले जायेंगे पैसे देने का तो सवाल ही नहीं है। खैर, मैं कहना नहीं चाहता कर्त्तव्य को छोड़ करके अधिकारों की लड़ाई ने भी हमारे देश में बेकारी बढ़ा रखी है। हमें कर्त्तव्य भावना लोगों में लानी चाहिए। मैं कहां ईमानदारी का उदाहरण तो जापान में देख कर आया हूं। वहां चौराहों पर अखबार रखे हुए थे और शाम को खाली बचे हुए अखबार और पैसे लेकर वे चले जाते थे। मेरे देश में क्या ऐसी भावना है कि अखबार रख दिए जाएं और शाम को बचे हुए अखबार सब पैसे मिल जाएं? ईमानदारी और देशभक्ति के भी मैंने अनेक उदाहरण देखे हैं। जापान में यह काली पट्टी बांध कर स्ट्राइक करने वाले स्ट्राइक करते हैं। हर साल वहां के लोग स्ट्राइक करते हैं। सरकार भी समझ जाती है लेकिन कारखानों में काम कभी बंद नहीं होता। वे काली पट्टी बांध करके अपना रोष व्यक्त करते हैं लेकिन काम बंद नहीं करते। अब या तो वह एक रास्ता है कि व्यक्तिगत संपत्ति न हो सब राष्ट्र की हो और फिर राष्ट्र जैसे चले वैसे चलायें। मगर उससे लोग विमुख हो रहे हैं और मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। दूसरा तरीका तो यह है कि हम अपनी पढ़ी को कर्त्तव्य-परायण बनाएं। अधिकारों के लिए हम सारी लड़ाई न लड़ें। अधिकारों के लिए क्या-क्या लड़ाइयां हैं उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो बीस प्वाइंट प्रोग्राम है उनमें से मैंने हमेशा दो प्वायंट्स पर ही जोर दिया है। पब्लिक में भी और आज यहां इस सदन के माध्यम से भी मैं यह बताना चाहता हूं कि दो प्वायंट्स बहुत आवश्यक है। मैं यह नहीं कहता कि 20 प्वायंट अनावश्यक हैं लेकिन दो प्वायंट मैं बहुत जरूरी मानता हूं वह है इस देश में अनुशासन और उत्पादन। उत्पादन से अभिप्राय आदमियों की पैदावार से नहीं है कहीं श्रम मंत्री जी गलत समझ जाएं उत्पादन से अभिप्राय खेत और कारखानों के उत्पादन से है। आदमी का उत्पादन हमें कम करना है

है और खेत-कारखाने में उत्पादन बढ़ाना है। इसकी तरफ हमें समाज को और राष्ट्र को लाना ही पड़ेगा और उसके लिए व्यापक रूप से व्यवस्था और समाज व्यवस्था को सभी को हमें साथ ले करके चलना पड़ेगा।

उप सभाध्यक्ष महोदया, मेरे देश में सत्ता और सम्पत्ति को जो सम्मान है श्रम और सेवा को उतना सम्मान नहीं मिल सका है। धन से धन कमा रहे है और पैसे से पैसा कमा रहे है। एक पैसे वाला उद्योगपति कितने ही लाईसेंस ले करके कितनी ही इंडस्ट्रीज बढ़ाता चला जाता है। क्यों नहीं पाबंदी लगाई जाए कि एक आदमी एक लाइसेंस से ज्यादा नहीं ले पायेगा। इसी तरह से और भी धांधलेबाजीया है कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा भी हम काम करवाना चाहते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में तो यह अच्छा है और वह मेरी समझ में आता है लेकिन बाकी कोआपरेटिव सोसाइटीज में थोड़ा-सा अधिकार ही अधिकार है और कर्त्तव्य की भावना कम है। यह पाबंदी हम कर सकते हैं। पैसे से पैसा न कमाया जाए श्रम से धन उपार्जन किया जाए। जो धन है हमारे यहां वह खेत और कारखाने की पैदावार को हम मानते थे। गांवों में पशु भी धन कहलाता है। धन किधर जा रहा है, धन कहां जा रहा है, धन क्या है यह नोट देना नहीं है। किसी देश की नोट सम्पत्ति नहीं है। नोट तो नासिक में छपता है और हमारे यहां नौएडा में भी छपने लगा है। नोट कितना आप छापेंगे लेकिन क्या इससे देश की समृद्धि बढ़ पायेगी ? बल्कि जितना नोट बढ़ेगा उतना ही महंगाई भी बढ़ती चली जायेगी क्योंकि खेत और कारखाने की पैदावार तो बढ़ेगी ही नहीं। नोट बढ़ते चले जाएं तो नोट खरीदने की शक्ति जिनमें आती चली जायेगी वे महंगाई बढ़ाते चले जायेंगे और गरीब पिसता चला जायेगा। जिसके पास कि नोट नहीं है। वास्तविक धन और सम्पत्ति तो खेत और कारखाने वाली चीज है। यहां भ्रम यह हो गया है कि नोट ही नोट है और नोट के लिए आदमी बड़े से बड़ा अपराध कर रहा है और नोट पैदा कर रहा है। इस विचारधारा को हमें बदलना पड़ेगा। उप सभाध्यक्ष जी, जवानों में कर्त्तव्य-परायण के लिए मैं कभी-कभी वैसे नहीं, व्यंग्य में तो कभी-कभी कह देता हूं, जब फारेस्ट मिनिस्टर था, मथुरा में एक तकरीर हो गई। मेरे पास कुछ जवान लड़के आ गए। मैंने जवानों से कह दिया और आज भी मैं जवानों से कह देता हूं, मैं डरता-डराता नहीं हूं, मैं कहने लगा कि तुम मुंह देखने और बाल बनाने के लिए शीशा-कंघी तो रखते हो कैंची-उस्तरा भी मुझ से ले जाओ और नाई की दुकान हैं खोल लो। ऐसा मैंने बोलते-बोलते कह दिया तो अखबारों ने हेडलाइन दे दी कि मिनिस्टर ने जवान लड़को से नाई का पेशा हजामत बनाने का करने को कह दिया।

हजामत बनाने को कह दिया। अखबार में हैडलाइन छप गयी। मुझे पता ही नहीं कि अखबार में छपा है। मैं झांसी में चला गया कुछ दिन बाद, वहां मेरी सार्वजनिक सभा थी शाम को। जिन लोगों ने सभा का आयोजन किया, मैं ललितपुर से बोलकर जरा देर में आया, तो मुझे वहां सभा आयोजन करने वाले एक वकील थे, कहने लगे--विकल साहब, तुम्हारी सभा तो आज बहुत खराब होगी। मैंने कहा--क्यों खराब होगी ? तो बताया कि एक कम्युनिस्ट वकील हैं वह तुमसे बहुत नाराज बैठा है। कैसे बैठा है ? कि उसने अखबार की कटिंग हाथ में ले रखी है कि तुमने नौजवानों को हजामत का पेशा बताया, नाई का पेशा बताया, इसलिये वह बहुत नाराज है। मैं बोला--तुम पहले उसी को बुलवा दो। मेरी तकरीर तो तभी अच्छी बनती है, जबकि कोई आलोचना कर दे और तभी भगवान न जाने कहां से बुद्धि देता है।

तो उपसभाध्यक्ष महोदया, वह डरे हुए थे कि सब बिगड़ जायगा और कोई नहीं सुनेगा, उस कम्युनिस्ट वकील को लोग सुनेंगे। मेरा यह था कि पहले उसी वकील को बुलवा दो और मैं जिद पर आ गया। वकील बोल पड़ा--मेरा दिल बैठा जा रहा है, विकल साहब ने नौजवानों का बड़ा अपमान किया है, यह मथुरा की स्पीच की कटिंग

[श्री राम चन्द्र विकल]

मेरे पास है, इन्होंने नौजवानों को नाई का पेशा, हजामत का पेशा करने को कहा है। इस तरह की इधर-उधर की बातें कहकर मुझे बहुत कण्डम किया। मैंने उसके बाद औरों को भी बोलने का मौका दिया और वकील को लेकर उन्होंने भी थोड़ा बहुत सहारा लिया। जो पब्लिक को भड़कना चाहते थे। इसका रिकार्ड मौजूद है, झांसी में पूछा जा सकता है। मैं आखिर में बोला---वकील साहब। ऐसे वकील साहब को जो काला कोट दिन का रात को भी पहने बैठे थे सभा में, यह हो सकता है व्यस्तता में उतारने का मौका न मिला हो। मैं बोला--- वकील साहब, आप वकील है? बोले--- हां जी, वकील हूं। मैंने कहा---तुम कम्युनिस्ट भी हो? बोले--- हां जी, कम्युनिस्ट भी हूं। मैंने कहा--- मुझे तुम्हारे कम्युनिस्ट होने पर संदेह है, वकील के लिये मैं संदेह कैसे कर तुम काला कोट अभी भी पहने बैठे हो? अब वह घबराया। पहले मैंने कहा--- अव्वल तो मैं तुम्हें नौजवान नहीं मानता, फिर कम्युनिस्ट में भी संदेह है क्योंकि जिसका अखबार पढ़कर दिल बैठ जाय, उसे युद्ध में भेजा जाय तो क्या होगा? तुम तो वैसे ही बैठ जाओगे। महोदया, मैं थोड़ी बहुत चुटकी लेता हूं, यही बस डटकर रहता हूं, बाकी पब्लिक में तो मैं दिल खोलकर बोलता हूं। मैंने कहा--- दूसरा जवान और कम्युनिस्ट इसलिये नहीं मानता क्योंकि कम्युनिस्ट किसी पेशे को छोटा नहीं मानता और नाई के पेशे को तुमने छोटा समझ लिया। मालूम है, नाई की परिभाषा क्या है मेरे दिमाग में---कि नाई अखबार रखता है रेडियो रखता है और शीशा लगाकर रखता है अपनी दुकान में। क्यों रखता है रेडियो और अखबार, इसलिये कि जो क्यू में लगे हुए हैं लोग, उनका टाइम खराब न हो। वह लोग अपना अखबार पढ़कर दिल बहलायें, रेडियो सुनकर दिल बहलाये और जिसकी हजामत बनानी है, उसके लिये नाई को फुरसत रहे। इसलिए वह खुशहाल है, जो रेडियो और अखबार रखता है दुकान पर। दूसरी बात, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, जो आदमी की गर्दन को इधर से उधर मरोड़ सकता हो, सिर्फ नाई का पेशा ही ऐसा है कि कुर्सी पर बैठा कर किसी की गर्दन को मरोड़ सकता है। मैं तो जिनको स्पोण्डिलाइटिस की बीमारी होती है, उसको भी नाई की कुर्सी बताता हूं कि कुर्सी पीछे डाले रखे, दफ्तरों में जिनको यह बीमारी है, वह नाई वाली कुर्सी बनवाये ताकि दिन में दस-बीस बार पीछे को अपनी गर्दन कर लिया करे। तो जिस कुर्सी पर गर्दन डालकर वह बड़े से बड़े आदमी की गर्दन को कभी बायें मरोड़ता है, कभी दायें मरोड़ता है, गर्दन मुड़वाने का काम कोई किसी से करवा सकता है? यहां तो मैं नहीं कह सकता उस बात को, कि कोई गर्दन मुड़वाता है। मट्टू साहब, मैं नहीं कह सकता। पर नाई ही है, जो गर्दन मरोड़ सकता है और उस पेशे को कम्युनिस्ट होकर आप छोटा बताते हो।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हमारे पूर्वी जिलों की बात कहता हूं बिन्देश्वरी दूबे जी, बिहार की मैं नहीं कह सकता। कुछ जातियां ऐसी हैं, जो हल चलाने को अपमान मानती है और हल चलाने को गरीबी और छोटा होने की निशानी मानती हैं और हल छोड़ने को अच्छी निशानी मानती है। मेरे सहयोगी थे, साथी थे, जो आज दुनिया में नहीं है---श्री गेंदा सिंह जी, वह उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एक बार देवरिया में हल चलाया और अखबारों में निकला कि गेंदा सिंह जी ने एक परम्परा तोड़ी पूर्वी जिलों में, हल चलाना बड़ी जातियों का भी कुछ फर्ज है।

तो महोदया, हल चलाने वाला छोटा समझा जाता है, हजामत बनाने वाला छोटा समझा जाता है। पालिस करने वाला छोटा समझा जाता है। जापान में मैंने औरतों को नाई का पेशा करते देखा है। मैं तो वहां नहीं गया। मेरे कुछ साथी गए जिन्होंने मुझे यह बताया। मैं उनका

नाम नहीं बताऊंगा जिन्होंने हजामत करवायी। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस देश में पेशे को छोटा समझा जाता है वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उस देश के नौजवानों की बेकारी कैसे दूर हो सकती है।

महोदया, आज राजनीतिक पार्टियां भी खूब स्लोगन लगाती रहती हैं। आज हमारे विरोधी पार्टी के लोग नहीं हैं। अगर वह रहते तो इस महत्वपूर्ण विषय पर वे भी अपने सुझाव दे सकते थे। मुझे दुख है कि यहां बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष के साथी नहीं है। मुझे खुशी होती यदि वे सारे मतभेद भुलाकर बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चल रही चर्चा के समय वह उपस्थित रहते। ऐसे मौके कम आते हैं। मैं उनके सुझावों का आदर करता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदया, आप तो जानती हैं मैं अधिकांश समय बैठकर सुनता रहता हूं और सुन-सुनकर अच्छे सुझावों को ग्रहण भी कर लेता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां हल चलाना, पालिस करना या हजामत बनाना जैसे पेशे को जब छोटा समझा जाता है वहीं नारे खूब लगाए जाते हैं। कर्त्तव्य के लिए नहीं बल्कि अधिकारों के लिए लगाए जाते हैं। जब तक अधिकार और कर्त्तव्य एक दूसरे के पूरक नहीं बनते, देश खुशहाल नहीं हो सकता।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं थोड़ी-सी बात यहां हमारे पंजाबी भाइयों के बारे में कहना चाहूंगा। वे यहां शरणार्थी बनकर आए, लेकिन मैं तो उन्हें पुरुषार्थी बोलता हूं। वे यहां रास्ता नहीं जानते थे। उनके पास जमीन नहीं थी। वे यहां उजड़कर आए थे। लेकिन उनके अपने पुरुषार्थ से आज सारे देश के उद्योग उनके पास हैं, फार्म उनके पास हैं, नौकरियां उनके पास हैं। दुनियां में किसी भी देश में ये पंजाबी भाई मिल जाएंगे। पेशे को ये पंजाबी भाई छोटा नहीं मानते। जो काम इन्हें मिल जाय करने के लिए तैयार हैं। मैंने गाजियाबाद में देखा है, जिस दुकानदार से माल खरीदा और उससे नीचे के रेट पर बेचकर ऊपर वाले दुकानदार को नीचा कर दिया। वह नीचे वाला दुकानदार आज ऊपर आ गया। अगर ये पेशे को छोटा मानते तो ये उजड़े हुए हमारे पुरुषार्थी भाई कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाते। वे व्यापार उद्योग में हैं, राजनीति में भी अगुआई कर रहे हैं। ये थोड़े से गट्स होने चाहिए। हमें चाहिए कि हम कर्त्तव्यपालन करें। अपने पंजाबी भाइयों से सबक लें, जापान से सबक लें। तो मैं नहीं समझता कि हमारे देश में बेकारी और बेरोजगारी की कोई समस्या रह जाएगी। सरकार रोजी-रोटी दे, सरकार मां-बाप है, मैं ऐसा नहीं मानता। आज बेकारी क्यों बढ़ रही है? आज हमारे यहां सरकारी नौकरियों में सुपरवाइजरों की तादाद ज्यादा है और काम करने वालों की कम है। उसके ऊपर वह अधिकारी और उसके ऊपर दूसरा अधिकारी। आदेश पर आदेश चलते हैं। काम करने वाले की पीठ पर सबका बोझ पड़ जाता है। महोदया, मैं मकानों के निर्माण के लिए मिलने वाले कर्ज के मामले में आई०टी०ओ० पर एक दफ्तर में चला गया। मेरे एक मिलने वाले हैं, वे कहने लगे कि तुम्हारे जाने से सर्टिफिकेट वगैरा मिल जाएगा। वे कर्जा सारा अदा कर चुके थे और इस बारे में एक सर्टिफिकेट चाहते थे। मैं सवा दस बजे गया। हां एक चपरासी मिला। उसके साथ ऊपर-नीचे आता-जाता रहा। आप जानती है, उपसभाध्यक्ष महोदया कि मैं तो कुर्त्ता-धोती में रहता हूं। मुझे कोई एम०पी० तो समझता नहीं है। मैं भी जानबूझकर ऐसे ही भोला बन जाता हूं। वे गांव का आदमी समझते हैं। मैं बताता भी कम हूं उस दफ्तर में 11 बजे के करीब कुछ लड़के-लड़कियां आए। उन्होंने मुझे नीचे वाले दफ्तर में बैठा दिया। मैंने कहा कि जब आ जाएं तब मुझे ले जाना। आजकल तो आफिसेज में लड़के-लड़कियां चाय मंगवाते है, बिस्किट मंगवाते है। अंग्रेजी राज्य में किसी दफ्तर में सिगरेट नहीं पी जाती थी। कैंटीन नहीं थी, रिटायरिंग रूम्स नहीं थे। दस बजे घर से आकर चार बजे घर जाते थे। तो लड़के-लड़कियों ने चाय और बिस्किट मंगाए। मैं चुपचाप बैठा रहा। इसी बीच एक मिलने वाला आया और कहने लगा अरे बिकल साहब यहां कैसे?

[श्री राम चन्द्र विकल]

और फिर कह दिया कि मैम्बर पार्लियामेंट हैं, तो वह लड़के-लड़कियां मेरी तरफ आ गये । अरे साहब, हमारी तो बड़ी मांगें हैं । तो मैंने कहा कि बताइये क्या मांगें हैं ? हमारे यहां हम पर काम का इतना बोझ है, आप यह बढ़वाओ, वह बढ़वाओ । मैं चुप करके सुनता रहा, उनकी सारी मांगें ले लीं । मैं बोला मेरी सच्ची सिफारिश चाहते हो तुम लोग, मैं तो जाकर यह कहूंगा, कि यहां कुछ कम कर दो बेकार लोग हैं । यह बताओ कि तुम पौने ग्यारह बजे आये हो और आकर के चाय-बिस्किट पीने लगे, कोई फाइल मंगाई तुमने ? तुम बैठे हो और कहते हो कि और बढ़ा दो हमारे दफ्तरों में काम करने वाल ? तो यह तो सुपरवाइजरों की तादाद इस देश में बढ़ती जा रही है, काम करने वालों की संख्या बहुत कम है – चाहे दफ्तर की हो या फील्ड वर्कर की हो यह सुपरवाइजरों की तादाद भी हमारे देश में बेकारी को कुछ रोके हुये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर देश का आर्थिक ढांचा खराब होता चला जा रहा है । आर्थिक विषमतायें बढ़ती चली जा रही हैं । मुझे श्रद्धांजली देने जाना है पृथ्वी सिंह आजाद की । मैं आज समय नहीं देना चाहता मेरे यह मन की भावनायें चाहे किसी भाई को बुरी लगी हों, मैं क्षमा चाहता हूं, पर राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र कर्तव्य परायणता से आगे बढ़ता है, त्याग और तपस्या से बढ़ता है । नौजवान लड़के-लड़कियां देश भक्ति के लिये मिट जायें जापान की तरह से या पंजाबी भाईयों से सबक लेकर के आगे बढ़े और जो हमारी रूढ़िवादिता पुरानी बातें – काम करने वाला छोटा आदमी और न काम करने वाला बड़ा आदमी – इन मान्यताओं को भी बदलना पड़ेगा और संविधान में कुछ बिदेश्वरी दूबे जी बदलवा सकें तो मैं उनका सहयोगी हूं ।

मैं अजीत जोगी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर उन्होंने यहां चिंतन करने के लिये रखा । हमारे उद्योग धंधे क्यों नहीं आदिवासी क्षेत्रों में जाकर खोले जाते ? सब दिल्ली में क्यों खुल रहे हैं ? 3000 अन-अथोराइज्ड इंडस्ट्रीज यहां दिल्ली में इंजीनियरिंग में उद्योग लगा दो, बिजली दे दो, शहर में ही बसते चले जायेंगे । वहां 10-10 मील के लोग पैदल चलकर साइकिल पर आकर वहां नौकरी करेंगे । दिल्ली जैसी आबादी, कलकत्ता, बम्बई या मद्रास जैसे शहरों में भीड़ नहीं होगी, वायु प्रदूषण नहीं होगा, गांव में आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग लगायें और वहीं से शहरों का मुंह गांव की तरफ मोड़ दो, बेकारी दूर होती चली जायेगी ।

मैं अनेक सुझाव दे सकता हूं परन्तु मेरे यह छोटे-मोटे सुझाव है, इन पर श्रम मंत्री जी भी विचार करें और केन्द्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर विचार करें, पर कर्तव्य परायणता को बल दें । कह दीजिये कि सरकारी नौकरियों में वही लिया जायेगा जो गांव में सड़क पर श्रमदान करके आयेगा । हम तो आजादी के समय श्रमदान करते थे, झाड़ लगाते थे चक्की चलाते थे, टट्टी उठाते थे, चरखा चलाते थे । गांधी जी ने बहुत पहले सोच लिया था कि आजाद होने के बाद अगर देश की आर्थिक आजादी नहीं आई तो राजनीतिक आजादी खाली काफी नहीं है, यह गांधी जी जानते थे, जवाहर लाल जी जानते थे, हमारी सारी कांग्रेस पार्टी जानती थी । इसलिये गांवों में जाकर झाड़ू लगवाना खड्डे खोदना, सड़क बनवाना, स्कूलों की इमारत बनवाना, तमाम ऐसे रचनात्मक काम हैं जो आजादी से पहले लोगों ने किये । आजादी के बाद भी उन गांवों को प्रियारिटी दीजिये जो श्रमदान करें, उनकी सड़कें पहले बनवायें, अस्पताल वहां पहले बनवायें और नौकरी उनको पहले दो । पर सर्टिफिकेट भी यहां जाली बन जाते हैं कर क्या ? श्रमदान के सर्टिफिकेट लेने लगें तो वह भी फर्जी बनवा लायेंगे लोग । चरित्र निर्माण सर्वोपरि है, कर्तव्य परायणता सर्वोपरि है । इसकी तरफ हम शिक्षा से, शिक्षा कैसी हो ? शिक्षा ऐसी हो जो कर्तव्य परायणता की ट्रैनिंग दे और श्रमदान से मुंह न चुराती हो । हम बच्चों को स्कूलों में, कालिजों में, यूनिवर्सिटियों में इस तरह की शिक्षा दें । सरकार, कानून और समाज,

मे सारे अंग मिलकर करके इस राष्ट्र की बेकारी को दूर कर सकते हैं। मैं फिर आपका आभारी हूं ।

श्री सोहन लाल धूसिया (उत्तर प्रदेश) : उप सभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । यह हमें मालूम नहीं है कि हर पंचवर्षीय योजना में इसका फिगर है कि नहीं कि बेरोजगारी में कितने लोग रहे। अगर इसका आंकड़ा रखा गया होता हर पंचवर्षीय योजना में, तो मेरा पूरा विश्वास है कि यह बढ़ती ही गई होती। चाहे वह अनस्किल्ड रहे या स्किल्ड रहे या सेमी-स्किल्ड रहे । किसी भी पंचवर्षीय योजना में यदि कंपैरिजन किया जाता है तो इससे भी मालूम होता कि बेरोजगारों की तादाद बढ़ रही है या घट रही है और उसके लिये सरकार भी कुछ करती । लेकिन जो सरकार चलाने वाले हैं, हमको उनसे ज्यादा तकलीफ है । बेरोजगारों की समस्या उतनी नहीं है जितनी कि जो सरकार चलाने वाले हैं उनसे है । जिन्होंने बागडोर संभाली थी वह गांधियन प्रिंसिपल पर चल रहे थे । गांधी जी के जो फौलोअर थे उनमें डिगनिटी आफ लेबर की कद्र थी । लेकिन जो आज के शासक हैं इन्होंने न तो लेबर की कद्र की, न लोगों से उसके लिये कहा । उसका रिजल्ट यह रहा कि जो लोग हाथ से काम करते रहे, मेहनत करते रहे उन लोगों को हेय दृष्टि से देखा गया । इस लिये लोगों में डिगनिटी आफ लेबर आ न सकी जो कि आनी चाहिये थी ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए]

श्रीमन्, हम समझते हैं कि यदि हर पंचवर्षीय योजना में इसको दूर करने के लिये कोशिश की जाती तथा अर्थशास्त्रियों की कुछ मीटिंग की गई होती, युनिवर्सिटी के जो अच्छे अच्छे इकानामिस्ट जो प्रोफेसर थे उनकी मीटिंग की गई होती, उनका सैमिनार किया गया होता, उनसे पूछा जाता कि क्या किया जाय जिससे हम बेरोजगारी की समस्या को कुछ दूर तक हल कर सकें तो अवश्य ही इसका कुछ हल होता। जो मंत्री है इनको तो फुर्सत नहीं है । लेकिन जो इनके हाथ पांव थे उन्होंने ख्याल नहीं किया । यह नहीं है कि यह अनजाने में किया, वह केयरफुल केयरलैसनैस थी । इस चीज को मैं अच्छी तरह से कह रहा हूं कि जो अनदेखी की गई वह केयरफुल केयरलैसनैस थी । इसलिये कि अगर यह बेरोजगारी की समस्या दूर हो गई होती तो उनके यहां कार्य कौन करता ? जमीन तो नेचुरल चीज है, हवा नेचुरल है, वाटर नेचुरल है । लैंड पर थोड़े से लोगों का अधिकार है, कुछ ही लोगों का कब्जा है। यही जब लोग देखते हैं तो नक्सलाइट की आग सुलग गई है । तो बेरोजगारी की समस्या, अमीरों के लिये खतरे की घंटी है। मैं बता रहा हूं कि बेरोजगारी की समस्या अमीरों के लिये खतरे की घंटी है । अगर अमीर आज पैसे वाले हैं तो वे अगर इन लोगों के लिये दवा-मीडिया नहीं निकालेंगे तो वे बच नहीं सकते हैं । आपको पता है कि जार फैमिली का क्या हुआ रूस में । रूस में रेवलूशन हुआ तो जार का क्या हुआ। मंत्री जी के क्षेत्र में, गर्दनीबाग में गोली से मार दिया जाता है । वहां नक्सलाइट गोली से मारते हैं महज इसलिये कि वे बेरोजगार हैं । कुछ उनसे दुश्मनी हो गई है और लोग भड़क उठे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहां इंटलिजेंट लोग नहीं हैं । अगर ये लोग अर्थशास्त्रियों से, इकानामिस्ट से अच्छे अच्छे टीचर्स से पूछें तो रास्ता निकालेंगे, लेकिन ये लोग जान-बूझकर नहीं करते । जान-बूझकर क्यों नहीं करते, यह मेंटलिटी का फर्क है । जिस सदस्य ने यह रेजलूशन दिया है वह भी कभी गवर्नमेंट सर्विस में थे, कलेक्टर थे, लेकिन उनकी भावना से जाहिर होता है कि वह नौकरी छोड़कर यहां आये तो इस लिये कि उनके दिल में दर्द है गरीबों के लिये दर्द है । हम तो ऐसे आदमियों के कृतज्ञ हैं, और लोगों को कृतज्ञ होना चाहिये । आज मैं इत्तफाक से मेडिकल इंस्टीट्यूट गया था । वहां पर मैंने एक डाक्टर से मुलाकात की । उसने अपनी सारी प्रापर्टी गरीबों को दे दी है । मरने के बाद कोई अपनी प्रोपर्टी नहीं ले जायेगा । यह जो अमीर हैं अमीर होते जा रहे हैं गरीबों को नोच कर ।

[श्री सोहन लाल धूसिया]

मंत्री जी हम यहां एक-दो बात कहेंगे। मैं बड़ा कृतज्ञ हूंगा यदि मेरी बात आप प्रधान मंत्री जी तक पहुंचा दें। देश गरीबों का है, यह कहा जाता है। गरीबों से ही सरकार बनती है। सरकार बनाने में हम समझते हैं 95 परसेंट अमीर लोग होते है। देश गरीबों का है। वोट गरीबों की है। सरकार चलाने वाले 95 परसेंट अमीर होते हैं। वह क्या गरीबों के लिये सोचेंगे? मजबूर न करिये कि गरीब अपना रास्ता खुद निकाले। अगर गरीब रास्ता निकालेगा तो रूस के जार जैसी हालत होगी। अक्ल आपके पास है, पावर आपके पास है। आप सोचिये इस चीज को कि जो गरीब स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड लोग जो बेकार है इनको कैसे रास्ते पर लायें।

मंत्री जी गांधीवादी हैं। मुझे पूरा विश्वास है वह जेल गये है। जेलखाना जाने वालों में एक भावना होती है कि गरीबों की तरफ झुके। पंडित नेहरू जैसे लोगो ने अपनी अमीरी लात मारी, गरीबों के बीच गये। आधी जिन्दगी अपनी गरीबों के लिये जेल में बिता दी। गांधी जी ने कहा था कि गांवों में रोजगार दो। लेकिन हम देख रहे हैं सारे रोजगार शहर में आ रहे हैं। यह कैसे आ रहे हैं? इंडस्ट्रीज सारी शहरों में हैं। इनको देहात में ले जाइये। मंत्री जी अगर कोई इंडस्ट्री शहर में लेकर आता है तो आप उसको बिजली पानी मत दीजिये। उनके लिये कोई इंतजाम मत कीजिये। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमारे प्रोफेसर ने पढाया था – स्ट्रेटजिकल प्वाइंट आफ व्यू से भगवान न करे कि वह दिन आये, वार के टाइम में अगर इंडस्ट्री एक साथ एक ही शहर में लगी होगी तो एक बम इसे सारी बरबाद हो जायेगी। इन इंडस्ट्रीज को दो-दो, तीन-तीन, मील की दूरी पर होना चाहिये। आजकल यह एक शहर में ऐसे खुल रही है जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हों। जो लोग पावर में है, जो इंडस्ट्रीज के लिये लाइसेंस देते हैं, जो बिजली देते है, पानी देते हैं, उनको सोचना चाहिये। इन को कुछ नहीं मिलना चाहिये। उनको सोचना चाहिये कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं हैं। मान लीजिये कोई दुश्मन हम पर हमला करता है तो एक ही बम से कई इंडस्ट्रीज खत्म हो जायेगी। अगर दो-दो, तीन-तीन मील की दूरी पर होंगी तो इससे अनएम्पलायमेंट प्रोब्लम भी सोल्व हो जायेगी, वहां के लोगों का डवलपमेंट भी होगा, लोगों में जागृति आयेगी। ये जो यहां के हुक्मरान हैं इन्होने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। इनके ध्यान न देने की वजह से यह समस्या विकट होती जा रही है।

आप दूसरे देशों की दूसरी चीजों में नकल करते हैं तो अनएम्पलायमेंट की प्रोब्लम सोल्व करने में उनकी नकल क्यों नहीं करते। कई देशों की हमारे से ज्यादा पापुलेशन है जैसे चीन है। आप देखिये उन्होंने कैसे यह प्रोब्लम सोल्व की है। स्किल्ड के मामले में जापान से सबक लीजिये और यह प्रोब्लम सोल्व कीजिये। तब ही हम अनइम्प्लायमेंट के प्रोब्लम को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि हमारे यहां एक से एक बड़े विद्वान हैं, लेकिन इन्होंने अनइम्प्लायमेंट के प्रोब्लम को सोल्व करने के लिये कोई ठोस सुझाव नहीं दिया है। अगर गौर करते तो हर पंचवर्षीय योजना में अर्थशास्त्रियों और इकानामिस्टस की मीटिंग करके सेमिनार करते, उसको सरकुलेट करते और कहते कि इस इस तरीके से हमगांवों में रोजगार दे सकते हैं। लेकिन गांवों का रोजगार छीना गया है। विशेषकर मंत्री जी आपसे मैं इस बात को कहूंगा कि आप अपने मंत्री मंडल की मीटिंग में मेरा नाम ले लीजिये कि उसने कहा है। यहां के मंत्री ने या यहां के डिपार्टमेंट ने गरीबों की, लाखों गरीबों के रोजगार को छीना है। रेलवे में पहले जो कुल्हड़ चला करते थे जिनको हिन्दुस्तान के लाखो कुम्हार सप्लाई करते थे और अपने बच्चों की परवरिश करते थे उनको रोजगार महज दो फैक्टरियों ने छीन लिया है। आप इस पर सोच लीजिये। प्लास्टिक की फैक्टरियों ने छीन लिया है। इसमें हम चाय पीते थे, पानी पीते थे। अब आप प्लास्टिक के कप में चाय पीजिये और जरा भी ठीक तरह से नहीं पकड़ेंगे तो चाय आप के ऊपर गिर जायेगी। एक बड़े लीडर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुल्हड़

की चाय लाओ, वह बड़ी सोंधी होती है। मंत्री जी आपकी कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटि है और हम आपको इसमें घसीट कर लाते हैं। आप अपने रेलवे मंत्री से बात कीजिये। रेलवे मंत्री ने किया या रेलवे मिनिस्ट्री ने किया या किसी अफसर ने किया, आपने लाखों को रोजगार दिया नहीं यह मैं आप पर चार्ज लगाता हूं। आपने लाखों का रोजगार छीन लिया है। जरा सोचिये। इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं। मंत्री जी आपको भी इसका खामयाजा भुगतना पड़ेगा। इसको आप याद कर लीजिये। जब कुल्हड़ में चाय मिलती थी तो वह आठ आने में मिल जाती थी, अब एक रुपये में मिलती है। मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी किया था। प्लास्टिक का गिलास 22 पैसे में मिलता है जब कि मिट्टी का कुल्हड़ पांच पैसे में होता था। जबर्दस्ती हमारा पैसा छीना जा रहा है। मतलब यह है कि डाकू से कहा जा रहा है कि डाका डालो, हम तुम्हें बचाने वाले हैं। मंत्री जी, आपकी कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी के नाते आप हमारी इस बात को पहुंचा दीजिये और खास कर इसको रिवाइज कर दीजिये। गरीबों का रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए। लाखों कुम्हारों का रोजगार छीना गया है।

. . . . . .

मैं दो चार बातें और कहना चाहता हूं।

. . . . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : तीन सदस्य और बोलने वाले हैं। यह आज खत्म हो जायेगा। नेक्स सेशन में नहीं लिया जा सकता है।

. . . . . .

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : आज थोड़ी देर और बैठा दीजिये, 6 बजे तक कर दीजिये।

. . . . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : नान-आफिसियल बिजनेस नहीं बढाया जा सकता है। मैं तो यह बता रहा था कि अभी तीन सदस्य और बोलने वाले हैं। 5 बजे तक आप बोल सकते हैं।

श्री सोहन लाल धूसिया : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में जमींदारी एबोल्यूशन हुआ। मैं कुछ दिनों तक यू.पी. एसेम्बली का मेम्बर था। मुझे भी सिलिंग की जमीन की कुछ इक्वायरी करने का मौका मिला था। आप विश्वास मानिये, एक जमींदार ने अपने एक कुत्ते का नाम मंगरू रखा था। मैं उस गांव में गया तो उस गांव के एक आध लोगों ने मुझे बताया कि आप जमींदार साहब से पूछिये कि थोड़ा मंगरूआ को बुला दीजिये। मैंने जब कहा कि क्या आपने मंगरू को देखा है तो उन्होंने मंगरू की जगह उस कुत्ते को बुला दिया कि यह मंगरू है। मैंने कहा कि क्या इसी के नाम पांच बीघा जमीन है तो कहने लग कि अगर पांच बीघा जमीन उसके नाम नहीं रखेंगे तो उसको क्या खिलायेंगे। आदमी को नहीं मिलता लेकिन कुत्ते के लिए है। यही हालत यहां पर है। खाली कागजों में लैंडसीलिंग हुई है। जमीन जिसके पास थी उसी के पास है और यह सब तैयारी हो रही है दूसरे रास्ते के लिए। यह सब अमीरों के लिए खतरे की घंटी है। सरकार चलाने वालों को ज्यादा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए जो इस तरह से कर रहे है। उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जमींदारी एबोल्यूशन के बारे में कहना चाहता हूं कि शहरी जमींदारी तो खत्म होने की नहीं है। मैं समझता हूं कि जब तक 51 प्रतिशत गरीबों के रिप्रजन्टेटिव कैबिनेट में नहीं आयेंगे तब तक शहरी जमींदारी जा नहीं सकती है। शहरी जमींदारी अगर नहीं जायेगी तो खूनरेजी होगी और यह सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसकी जिम्मेदारी गरीबों पर नहीं होगी। वह मजबूर है करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके लड़के गुलछर्रे उड़ायें और उनके बच्चे उपवास करें वे भूखों मरें। ऐसा नहीं हो सकता है। भूखी जनता को देशभक्ति सिखाने वाली भूख इंसान को गद्दार बना देती है। आप भूलिये मत कि इस देश में कितने कुकर्म हुए है, कुछ तो भूख से मरने वालों ने, जो भूख से मर रहे थे उन्होंने किये, लेकिन ज्यादा गद्दारी जो बड़े-बड़े लोग थे उन्होंने की है।

[श्री सोहन लाल धूलिया]

बेरोजगारी दूर करने के लिए मैं कुछ अपनी तरफ से सुझाव दे रहा हूं। जिस खानदान में वहां का मुखिया मर जाता है और जब उसकी प्रापर्टी इनहेरेंट होती है तो मैं कहना चाहूंगा, मंत्री जी इस चीज को देख लें, इस सुझाव को मान लें, मालूम नहीं कौन सा सुझाव मंत्री जी को पसंद आयेगा, पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। मेरा सुझाव यह है कि जब पिता की मृत्यु हो जाय तो एक लड़के की जगह पर विनोबा भावे की मानें। अगर चार लड़के हैं तो उस प्रापर्टी के 5 हिस्से किये जायें और एक हिस्सा विनोबा भावे के नाम लगाया जाय और उस जगह पर इंडस्ट्री खोली जाय और वहां पर अन-इम्पलाइड लड़के काम करें। इससे कुछ हद तक बेरोजगारी दूर होगी। दूसरा, जितने पढ़े लिखे लड़के हैं वे आज गांवों से भाग रहे है और शहरों की तरफ जा रहे हैं मैं गवर्नमेंट से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह स्टेट गवर्नमेंटस को यह सलाह दे उनकी सलाह उनके लिये आदेश होगा कि हर जिले में 6 महीने की, 3 महीने की, जितनी भी मुनासिब हो, ट्रेनिंग देकर पढ़े लिखे लड़कों को गांवों में दवा खोलने की इजाजत दी जाय। गरीब लड़का यदि वह मैट्रिक पास है तो वह पेटेंट दवाओं का दवा-खाना अगर खोलना चाहे तो वह नहीं खोल सकता है थोक दुकान तो खोल सकता है लेकिन फुटकर दुकान नहीं खोल सकता है। यह इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ साठ-गांठ है। अगर फुटकर दुकान उसको ट्रेनिंग देने के बाद खोलने की इजाजत दे दें तो वह इम्पलाइड हो सकता है और उसकी बेरोजगारी किसी हद तक दूर हो जायेगी। मैं नहीं जानता हूं कि यह मेरे ही दिमाग में क्यों है। आप लोग ज्यादा सर्विस करते हैं। यह बात आप लोगों के दिमाग में पहले आनी चाहिए थी। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर जरा गौर करें।

आजकल बैंकों से कर्जे दिये जा रहे हैं। आप यह कर्जा देते हैं ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप एक ट्रेनिंग सेंटर हर ब्लाक में खुलवायें। जो लड़के ट्रेनिंग न लें उनको आप बैंकों से कर्जा मत दिलवाइये। लेकिन जो वहां पर ट्रेनिंग ले लें उनको 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार जो भी आप दे सकते है वह कर्जा उनको दे सकते हैं। इस प्रकार से वे पढ़े लिखे लड़के गांव में सैटल हो सकते हैं। अनइम्पलाइमेंट कुछ हद तक दूर होगी, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे है? कैसे करेंगे, यह हम नहीं जानते है।

फिर भी मैं पेंशन के लिए बात कर रहा हूं। हम तो यह कहेंगे कि आप बुढ़ापे में भी उनको पेंशन मत दीजिए। पेंशन देने का एक तरीका कर लीजिए। उनसे तीन घंटे आप चर्खा चलवाइये। बस से काम उनका और उनके परिवार वालों का कपड़ा निकल जाएगा। अम्बर-चर्खा कुछ भी आप चलवाइये उनको तब पेंशन दीजिए। जो सूत न दे, उसको आप बुढ़ापे की पेंशन मत दीजिए।

इसी तरह से जो अबला है, उनके लिए भी यही करिये। यह बहुत मेहनत का काम नहीं है, बैठकर हाथ घुमाना है, चर्खा चलाना है, गांधियन थियरी है। उसमें हम उनको रोजगार देंगे। इन सब चीजों को आप करिए। हो सकता है कि कुछ अनइम्पलायमेंट का प्राबलम साल्व हो, लेकिन जिस तरह से चल रहा है कि जमीन फैली पड़ी है—मैं तो यहां से जब लखनऊ जाता हूं, तो देखता हूं कि शाहजहांपुर से लखनऊ तक रेलवे लाईन के दोनों तरफ जमीन फैली पड़ी हुई है, लेकिन आप गरीब को देंगे नहीं और वह पटवारी के कागजों में सब किसी न किसी के नाम दर्ज होगी। आखिर क्यों नेशनलाइज किया जा रहा है? एक प्राइम मिनिस्टर कितना करेगा, एक मिनिस्टर क्या करेगा, लेकिन नहीं प्राइम मिनिस्टर की ताकत और मिनिस्टर की ताकत तो सब चली गई है, उसको लोग करें तब तो ना, जैसे विकल जी ने कहा कि लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे है। हम ड्यूटी सिखाने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको सिखाइये तो हाथ जोड़ कर सिखाइये।

अगर ऐसा नहीं करते हैं, जो तो हुक्मरां हैं दोषी वही कहे जायेंगे । हमें गल कुछ भी कहें, लेकिन आज भी हमें विश्वास है कि यह सुधरेगा, काश आप लोग भी, सुधर जाते—जो हुक्मरां हैं, जिनके हाथ में पावर है, अगर वह भी सुधार जाते तो इस तरह से देश की शक्ति बढ जाएगी । देश की शक्ति जब बढ़ेगी, तभी हम खुशहाल होंगे । आज हम गरीब क्यों कहे जाते हैं? खुशहाल तो हैं नहीं, काम है नहीं । हमें राजीव गांधी जी की रहनुमाई में उम्मीद है कि वह सुबह आएगी, जल्दी आएगी, जिसमें हर आदमी जो बरोजगार है, रोजगार पायेगा और वह खुशहाल रहेगा, हमारे देश की गरीबी मिटेगी । एक दो लाईन कह दें उस सुबह के लिए—

कई सुबह पे नजर है, पर हाय यह भी डर है,

यह सहर भी रफ्ता-रफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे ।

धन्यवाद ।

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन के सम्मानीय सदस्य, अजीत जोगी जी ने देश की गम्भीर समस्या को प्राइवेट मेम्बर्स रेजोल्यूशन के माध्यम से चर्चा का जो मौका लाया है, इसके लिए मैं अपनी तथा सदन के अन्य सदस्यों की ओर से उनका शुक्रगुजार हूं ।

देश में जो गम्भीर समस्यायें हैं, उनमें से बेरोजगारी एक बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है और यह केन्द्र सरकार के लिए राज्य सरकारों के लिए और आपके तथा हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का और चिंतन का विषय है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस पर न हमारा श्रम मंत्रालय केन्द्र का सीरियस है और न राज्यों के श्रम मंत्रालय इसमें सीरियस हैं क्योंकि हमारे देश में एक प्रथा है—देश में आजादी के बाद हर क्षेत्र ने तरक्की जरूर की है, लेकिन हमारी जो प्लानिंग है, जिस नियोजन के माध्यम से हम देश की तरक्की करना चाहते हैं, उसमें कुछ खामियां हैं । उनको मैं स्वीकार करना चाहूंगा । हमारे यहां समस्याओं को बढ़ने दिया जाता है । हमारे यहां समस्याओं को बढ़ने दिया जाता है और समस्या जब इतनी बढ़ जाती है कि उसमें कोई रास्ता नहीं निकल पाता है तब उस पर विचार किया जाता है कि इसमें कैसे रास्ता निकालें ? मैं इसके विषय में कहना चाहता हूं । आजादी के बाद डिफेंस के क्षेत्र में हम लोग कमजोर थे, हमारी सेनाओं तथा रक्षा उत्पादन पर जिस कोटा में हमें ध्यान देना चाहिये था वह हमने नहीं दिया तो 1962 में जब हमारी चीन से लड़ाई हुई और हमें उसमें हार महसूस करनी पड़ी तो उसके बाद ही हमने सोचा कि हमारी डिफेंस की लाइन कमजोर है । फिर हमने डिफेंस के क्षेत्र में तरक्की की, डिफेंस के उत्पादन के क्षेत्र में तरक्की की और आज सारे संसार में भारत डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है । दूसरी एक समस्या बताऊंगा कि आजादी के बाद इस देश में जो आबादी बढ़ रही थी, उस आबादी के बारे में हमने कभी नहीं सोचा कि आबादी की रफ्तार क्या है । पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि या दूसरे क्षेत्रों में हम कैसे तरक्की कर सकते है हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा और जब आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गयी और देश का अनाज का उत्पादन कम पड़ने लगा और 1970-72 में अमेरिका से, जो जानवरों को खिलाने वाला माल होता है, उसको भारत में लाकर यहां की जनता को खिलाना पड़ा तब हमारी आंखें खुली कि इस देश में कृषि के उत्पादन में हम पीछे हो गये है । फिर हमने कृषि के क्षेत्र में ध्यान दिया और आज हम कृषि के क्षेत्र में, अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुये हैं। तीसरा उदाहरण मैं दूंगा कि हमारे देश मे वन संपत्ति काफी बड़ पैमाने पर थी । विधि के विधान से या जो भी हमारे नियम है उनके अनुसार कम से कम 33 या 35 परसेंट देश में फारेस्ट रहना चाहिये अदरवाइज कहीं बरसात ज्यादा होगी, कहीं कम होगी कहीं गीला होगा, कहीं सूखा होगा । इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया । जंगलों की कटाई बहुत बड़े पैमाने पर हुई

[श्री नरेश सी० पुगलिया]

और आज यह नौबत आई है कि सारे देश में जंगल कटाई बन्द करनी पड़ी है और आज हम देश में जंगल किस प्रकार से बढ़ाने हैं इस पर सोच रहे है । इसी प्रकार से इस देश में जो बढ़ती हुई आबादी थी जिसके माध्यम से नयी पीढ़ी सामने आ रही थी, उन हमारे युवक साथियों को चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित, हम कैसे रोजगार देंगे इस विषय पर भी न केन्द्र सरकार ने और न राज्य सरकार ने कभी प्लानिंग की, न इस पर विचार किया । आज नौबत यह आयी है कि हमारे केन्द्र के श्रम मंत्रालय के माध्यम से जो आंकडे दिये गये हैं उनके अनुसार 3 करोड़ लोग हमारे यहां बेकार है । लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है इनको मिलाकर ऐसे बेकार युवकों की संख्या आज 5 करोड़ से ज्यादा है जिसमें 3 करोड़ तो रजिस्टर्ड हैं और दो या ढाई करोड़ दूसरे हैं । इस प्रकार से 5 करोड़ बेकार है मतलब 10 करोड हाथ इस देश में बेकार हैं उनका श्रम फालतू जा रहा है लेकिन एक चीज मुझ बड़े दुख के साथ कहनी पडती है कि हमारे देश में श्रम को जो मान्यता मिलनी चाहिये, उसको जो दर्जा मिलना चाहिये उसको देने में आज तक सफल नहीं हुये हैं । श्रम को हमने दूसरा स्थान दिया है और पैसे को पहला स्थान दिया है । पैसे की हम पूजा करते है और श्रम को एक बड़ी तुच्छ चीज मानते है, चाहे श्रम करने वाले व्यक्ति रहे या श्रम मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी रहे या श्रम मंत्री रहें, राज्य और केन्द्र के श्रम मंत्री के रूप में अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाती है – मैं दुबे जी के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि पिछले 40 साल से उन्होंने कामगार क्षेत्र में अपनी पूरी जिन्दगी लगा दी है, इंटक के अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मजदूरों के हितों में कई निर्णय लिए है – मैं भी कामगार क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं और मैं सब जानता हूं, मैं महाराष्ट्र में विधान सभा का सदस्य भी था, वहां भी हमने देखा कि श्रम मंत्रालय को एक घटिया मंत्रालय समझकर माना जाता है, श्रम मंत्री की जिम्मेदारी अगर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दी जाये तो उसे लगता है कि हमें कहां फंसा दिया, कौन सा मंत्रालय दे दिया । तो इस प्रकार से इस देश में श्रम की, श्रम मंत्रालय की, श्रम मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी की स्थिति है और जिनके लिये श्रम मंत्रालय बनाय गया है, चाहे वे बेरोजगार युवक हों, उद्योग में काम करने वाले कामगार या खेतों में काम करने वाले असंगठित कामगार, इनका किसी प्रकार से श्रम मंत्रालय में कोई दखल नहीं है । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर कोई मसला रखा जाए किसी भी पार्टी की सरकार राज्य में हो मुख्य मंत्री के समक्ष रखा जाए श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष रखा जाए अगर किसी उद्योग के कामगारों का मसला जाता है और उसके साथ उद्योगपति भी खड़े हो जाते है । जिस इंडस्ट्री में कामगारों का शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, उस उद्योग के कामगारों को न्याय देने के बजाय श्रम मंत्रालय के अधिकारी या श्रम मंत्री अगर किसी के हक में निर्णय करते हैं तो 98 परसेंट मामलों में मालिकों के हक में निर्णय होते है पूंजीपतियों के और उद्योगपतियों के हक में निर्णय जाते हैं कामगारों के हक में निर्णय नहीं जाते हैं । हमारे देश में इस प्रकार से श्रम मंत्रालय में एक कमी आ गई है । श्रम को हमारे देश में तुच्छ माना गया है इस विषय में भी गम्भीरता से हमें सोचना होगा । माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बिड़ला मेनेजमेंट में एक सीमेंट फैक्टरी है उसके मामले को लेकर हम संगमा जी के सामने आए राज्य के श्रम मंत्री के पास गये, मुख्य मंत्री के पास गये । दूबे जी ने भी मीटिंग बुलाई । अधिकारियों ने साफ-साफ कहा कि इसमें इंडस्ट्रीयल कोर्ट का इंटरिम स्टे है इसलिए हम मदद नहीं कर सकते । मुझ जान कर के बहुत दुख हुआ कि दूबे जी जैसे व्यक्ति श्रम मंत्री होने के बाद भी अधिकारी ने ऐसी हिम्मत कैसे की । 550–600 मजदूर बेकार बैठा हुआ है । सीमेंट वेज बोर्ड की मांग है, मान लो यूनियन ने गलती की या यूनियन के नेता की हैसियत से हमने

गलती की तो इसकी सजा 600 या 1000 मजदूरों को क्यों? उस विषय में चाहे केन्द्र हो या राज्य का श्रम मंत्रालय हो इनको श्रम मंत्रालय नहीं बल्कि मालिकों का पूंजीपतियों का मंत्रालय का नाम दे देना चाहिए। अब दूबे जी से हम अपेक्षा करते हैं कि श्रम मंत्री के रूप में इस देश के करोड़ों हाथ बेकार बैठे हैं उस विषय में आप एक्सपर्ट लोगों के साथ बड़े बड़े इकोनोमिस्टस को साथ लेकर हम बेरोजगार भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं, केन्द्रीय सरकार के माध्यम से क्या न्याय दिला सकते हैं इस पर आपको गम्भीरता से सोचना होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट चाहे केन्द्र का हो या राज्यों का हो इस पर इस तरह से नहीं सोचता होगा लेकिन एक सीनियर नेता के रूप में और मजदूर क्षेत्र में जो आपको 40 साल का अनुभव है आप उस क्षेत्र के अन्दर माहिर है जो हमारे यहां देश में बरोजगारी बढ़ रही है यह कोई छोटा मामला नहीं है मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि नक्सलवाद की समस्या है। मैं जिस जिले से आता हूं चन्द्रपुर गड़चरौली वह महाराष्ट्र का ऐसा एरिया है जहां नक्सलवाद की समस्या बढ़ गई है। हम लोकतन्त्र को मानने वाले व्यक्ति है मैं नक्सलवाद को गलत नहीं कहूंगा मैं सरकार की नीतियों को गलत कहूंगा क्योंकि इस देश में इस संसार में दो विचारधाराएं चलती हैं। जिनका लोकतन्त्र में विश्वास उठ जाता है। लोकतन्त्र के माध्यम से जनता को सुविधायें या न्याय नहीं दे सकते हैं तो वह सोचते हैं कि लोकतन्त्र ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारा शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है खास कर के पिछड़े हुए भागों में आदिवासी भागों में नक्सलवादी एक्टीविटीज सारे देश में हैं हर प्रान्त में हैं। दुबे जी बिहार के आप मुख्य मंत्री यह चुके हैं बिहार में यह समस्या हैं, आन्ध्र प्रदेश में तो कई आई.ए.एस. अधिकारियों को भी उठा ले गये थे, बंगाल में भी यह समस्या है, देश के कोने कोने में नक्सलवाद की समस्या है लेकिन हम ने गम्भीरता से नहीं सोचा। अगर हम मुख्य मंत्री से शिकायत करते हैं कि नक्सलवाद की समस्या हमारे यहां बढ़ती जा रही है, ठीक है, आप मेरे जिले चन्द्रपुर गड़चरौली में सन् 1981 में दो हजार एस.आर.पी. पड़ी है। बन्दूक से इस समस्या का हल नहीं हो सकता है आदिवासी क्षत्रों और पिछड़ क्षेत्रों में शोषण हुआ है, दमन हुआ है। हमारी विकास योजनायें वहां तक नहीं पहुंची हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि वहां का जो युवक है वहां जो नई पीढ़ी है उन्होंने न कभी बस देखी है न कभी रेलगाड़ी देखी है न कभी लाइट देखी है लंगोटी लगा कर रहने वाले आदिवासियों ने जंगलो की रक्षा की है। उपसभाध्यक्ष महोदय आप भी उस एरिया में मंत्री के रूप में जा चुके है आप जानते हैं कि सागवान का एक एक पेड़ जिसकी कीमत दो लाख रुपये है उसकी आदिवासियो ने रक्षा की है। करोड़ो रूपये का रेवन्यु राज्य सरकार को इससे मिलता है। आदिवासी भाइयों ने जंगलों की रक्षा की है न वहां इरीगेशन का कोई प्रोजक्ट है, हाई स्कूल या कालेज तो दूर की बात है बाल शिक्षा केन्द्र या प्राइमरी एजुकेशन तक की व्यवस्था वहां नहीं हुई है न इरीगेशन का साधन है न रोड का कोई साधन न बस सर्विस, ऐसे हालात में वहां की जनता का लोकतंत्र के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। एक ऐसा समाज भी है इस देश में और अन्य देशों में जो जानते हैं पढ़े लिखे युवक हैं कि नक्सलावाद में कौन हैं। जो भी है, पढ़े लिखे युवक जिनका शोषण हुआ है, दमन हुआ है उन्होंने देखा कि खूनी क्रांति के माध्यम से न्याय मिल सकता है। उन्होंने हाथ में बन्दक ली, हाथ में रिवालवर ली, स्टेनगन ली, मशीनगन ली। आज नतीजा क्या हुआ? चन्द्रपुर और गड़चरौली के जिले का 2/3 भाग उनके कंट्रोल में है। राज्य की सब पार्टियां फेल हो गयी हैं। गड़चरौली जिले में तो कोई भी राज्य की पार्टी अस्तित्व में नहीं है। वहां नक्सलवादियों का अस्तित्व है। इस चीज को सीरियसली कोई नहीं लेता। अगर विधायक या एम. पी. कोई आवाज उठाता है तो एस.आर.पी. की दो बटेलियनों की जगह पर चार बटेलियनें भेज दी जाती हैं।

(श्री नरेश सो० पुगलिया)

आपकी एस.आर.पी. रोड पर दौड़ेगी, जीप में दौड़ेगी लेकिन नक्सलवादी एक रात में 40-40 किलोमीटर पैदल चलते हैं, अन्धेरे में चले जाते हैं, जंगल के रास्ते जाते हैं। इस प्रकार से इस देश में अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो बरोजगारो के विषय को बड़ी गम्भीरता से लेना होगा। लेकिन हमारी सरकार और दुबे जी इसे कितनी गम्भीरता से लेते हैं यह तो पता नहीं। हां, मुझे उम्मीद है खासकर दुबे जी से जरूर उम्मीद है इससे सम्बन्धित जो मंत्रालय है उनसे इस बारे में बात करेंगे। हालांकि केन्द्रीय सरकार ने कई योजनायें एन.आर.ई.पी. और आई. आर.डी.पी. और दूसरी कई योजनायें बनाई हुई हैं ग्रामीण जनता के लिए। लेकिन वहां तक फल नहीं पहुंचता। बिचौलिये चाहे नेता रहे, अधिकारी, रहे पदाधिकारी रहे उस पर हाथ साफ कर जाते हैं, वहां तक पैसा नहीं पहुंच पाता। ग्रामीण क्षेत्र में अगर विकास नहीं होता है तो स्थिति सुधरेगी नहीं। एक पूर्व वक्ता ने कहा कि ग्रामीण पापुलेशन आज शहर की ओर भाग रही है। मेरा चन्द्रपुर और वलारपुर एरिया है। खासकर महाराष्ट्र हमारा एडवांस स्टेट है। यहां पर औद्योगिक क्रांति हुई है लेकिन शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं। देश के कोने कोने में ग्रामीण जनता शहर की ओर भाग रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं हैं। श्रम की प्रतिष्ठा न होने की वजह से वहां पर नहीं जाते हैं। मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि आपके बिहार में शिक्षा का परिमाण कम हो गया है, बेकारी और भुखमरी ज्यादा हो गई। लेकिन महाराष्ट्र जैसा एडवांस स्टेट जहां ग्रामीण क्षेत्र में आप को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैट्रीकुलेट की कोई कमी नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का परिमाण पढ़ा है लेकिन वह खाली हाथ का काम मांगते हैं, हम काम नहीं दे पाते। जहां-जहां औद्योगिक क्रांति हुई हैं, औद्योगिक विकास हुआ है, खासकर हमारे जिले में 30 हजार मजदूर कोल माइन्स में काम करते हैं, 7 हजार डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां पर थरमल पावर स्टेशन है, सीमेंट फैक्टरी है, वहां पर चन्द्रपुर जिले में तो मिल जाता है और विदर्भ के जो 7-8 जिले हैं वहां अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाते है तो लोग कहते हैं बताइये आपकी सरकार ने हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए क्या किया।

इस सदन के माध्यम से आपने 18 वर्ष वाले युवक को मतदान का अधिकार दिया है। यह बहुत अच्छी बात इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने की है। जो बेकार युवक है उसको मालूम होता है कि मैं इतने साल से बेकार हूं लेकिन मे पास पांच साल का एक ऐसा कार्ड है, ऐसा मतदान का अधिकार मेरे हाथ में है कि अगर सरकार युवकों के हित में, बेरोजगारों के हित में काम नहीं करती तो बदलने की शक्ति उनके पास है। इसका मैं स्वागत करता हूं। खासकर प्रधान मंत्री राजीव जी ने हमारी इस युवा पीढ़ी को यह मतदान का अधिकार दिया है। लेकिन इस अधिकार के साथ जब तक उनके पेट की भूख हम नहीं मिटा सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते, एक एक घर में 4-4, 5-5 लड़के बेकार पड़े हैं उनको रोजगार नहीं दे सकते, जिनकी जमीन हम उद्योग के लिए लेते हैं उनके बच्चों को नौकरी नहीं दे पाते तो उसका क्या लाभ। राज्य सरकारें चिल्लाती हैं कि जिनकी जमीन ली है उनको आपको नौकरी देनी चाहिए। उनको नौकरी नहीं मिलती है। कल मैंने स्पेशल मैंशन के माध्यम से कोल माइन्स के लिए वेस्टर्न कोल फील्ड की सरकार किसानों से जमीन लेती है वह तीन से चार हजार रुपये तक कीमत देती है जब कि मार्किट कीमत 15 से 20 हजार है। 30 हजार करोड रुपये का डिपोजिट मेरे अकेले डिस्ट्रिक्ट में है जिसका सर्वे हुआ है और जिसका सर्वे नहीं हुआ है वह अलग है। तो इस प्रकार किसानों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। महोदय, अगर हम बेरोजगार युवकों के लिए नियोजनबद्ध कोई कार्यक्रम नहीं दे पाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आनेवाले समय में आपको, हमको और इस देश की जनता को भुगतने पड़ेंगे। बेकार व्यक्ति हाथ में बंदूक उठाने में भी नहीं चूकेगा। महोदय, इस देश में गरीबी

और अमीरी में बहुत डिफरेंस है कि एक व्यक्ति के पास इतनी पूंजी है कि वह अपने बच्चों को दिन में दस बार भी खाना खिला सकता है और चार-चार गाड़ियां भी रख सकता है। लेकिन दूसरी जगह एक व्यक्ति को एक समय का खाना भी नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको इस विषय को गंभीरता से लेना पड़ेगा।

महोदय, इस वर्ष केन्द्र सरकार ने 120 जिलों में एक नयी योजना चालू की है। हमने पंडित जवाहर लाल जी के इस जन्म शताब्दी वर्ष में इसको एडाप्ट किया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। उसी प्रकार 8 परसेंट जो टैक्स लगाया है, रोजगार टैक्स, मुझे उम्मीद है कि इस पैसे का अच्छा उपयोग होगा और हम इसके द्वारा उनकी जरूर मदद कर पायेंगे।

महोदय, आखिर में एक और बात कहना चाहूंगा। मेरी श्रम मंत्रीजी से विनती है कि वे केन्द्रीय स्तर पर राज्य के श्रम मंत्रियों की एक मीटिंग बुलायें और इसमें विचार करें कि हम बेरोजगार भाइयों के हक में क्या कर सकते हैं? देश के बड़े बड़े इकोनोमिस्ट बुलाइये, देश के एक्सपर्टस बुलाइए और एक लंबी योजना तैयार कीजिए जिसके द्वारा हम अपने बेकार भाइयों की ज्यादा-से-ज्यादा मदद कर सकें। इस बारे में आपको श्रम मंत्रालय के अलावा वित्त, उद्योग और कृषि मंत्रालयों का भी सहारा लेना पड़ेगा।

महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो एक महत्वपूर्ण विषय हमारे साथी श्री अजीत जोगी ने उठाया है इस पर केन्द्रीय सरकार और खासकर श्रम मंत्री जी गंभीरता से विचार करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Before I adjourn the House, I wish all of you a very colourful Holi. Now the House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 27th March 1989.

The House then adjourned at two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 27th March 1989.